राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात,संस्करण शुक्रवार 13अगस्त-2021 वर्ष-4, अंक - 201 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
YouTube Linkedin
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

गंभीर पॉक्सो केस में किशोरों की उम्र 16 साल करने पर जोर नहीं

नई दिल्ली। एक प्रमुख संसदीय समिति ने गंभीर पॉक्सो मामलों में लिप्त किशोरों की आयु 18 साल से घटाकर 16 साल करने के लिए दबाव न डालने का फैसला किया है। इन किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों को सरकार के पर्याप्त बताने के बाद यह निर्णय सामने आया है। सरकार की प्रतिक्रिया राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणी पर आई है। समिति ने कहा था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत बड़ी तादाद में ऐसे मामले हैं, जिनमें किशोरों की आयु कानून लागू होने को लेकर तय उम्र से कम रही है। अगर नाबालिग यौन अपराधियों को सही परामर्श नहीं दिया गया तो वह ज्यादा जघन्य अपराध को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा, कानून के मौजूदा प्रावधानों पर पुनर्विचार महत्वपूर्ण है। ऐसे में गृह मंत्रालय आयु सीमा की समीक्षा के मुद्दे को महिला और बाल विकास मंत्रालय के समक्ष उठाकर देखे कि क्या इसे घटाकर 16 साल किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया, जेजे अधिनियम में जघन्य अपराध में लिप्त 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों के मामलों में फैसला लेने की प्रक्रिया भी शामिल है। सरकार की ओर से पेश इस जवाब के बाद समिति ने कहा, वह मामले पर आगे विचार नहीं करना चाहती।

EOS03 उपग्रहः इंजन में आई खराबी के चलते इसरो का मिशन रहा अधूरा

नई दिल्ली। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा EOS-03 उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम रहा। इससे इस मिशन को झटका लगा है। इंजन में खराबी के कारण समय से 10 सेकेंड पहले ही इसकी लॉन्चिंग टालनी पड़ी। इसे अंतरिक्ष से धरती की निगरानी करनी थी, इसीलिए इसे भारत की सबसे तेज आंखें भी कहा जा रहा था। लेकिन मिशन अधूरा ही रहा गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 5 बजकर 43 मिनट पर जीएसएलवी-एफ 10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण शुरू किया था। पहले दो चरण में ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन तीसरे चरण में इसके क्रायोजेनिक इंजन में खराबी आ गई। स्पेसप्लाइट नाऊ के

मुताबिक, इसरो EOS-03 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। इसरो ने पुष्टि की है कि जीएसएलवी एमके. 2 लॉन्च आज क्रायोजेनिक चरण में देखी गई खराबी के कारण विफल रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 के बाद से किसी भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण में यह पहली विफलता है। इससे पहले इसरो के लगातार 14 मिशन सफल रहे।

- **इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 5 बजकर 43 मिनट पर प्रक्षेपण शुरू किया था**
- **पहले दो चरण ठीक तरीके से आगे बढ़े, लेकिन तीसरे चरण में इसके इंजन में खराबी आ गई**
- **उपग्रह का उद्देश्य नियमित अंतराल पर बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय पर तस्वीरें उपलब्ध कराना था**

इसरो ने आज सुबह 5.43 बजे सैटेलाइट लॉन्चिंग शुरू की थी। तय समय के अनुसार सभी चरण पूरे होते चले गए। मगर तीसरे चरण में EOS-03के अलग होने से पहले क्रायोजेनिक इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से इसरो को आंकड़े मिलने बंद हो गए। इसके बाद इसरो प्रमुख ने ऐलान किया कि यह मिशन आंशिक तौर पर विफल हो गया है।

साल का पहला मिशन फरवरी में हुआ था

इससे पहले 28 फरवरी को इसरो ने साल के पहला मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। भारत का रॉकेट 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राजील का उपग्रह लेकर अंतरिक्ष रवाना हो हुआ था।

ब्राजील के अमेजोनिया-1 और 18 अन्य उपग्रहों को लेकर भारत के पीएसएलवी (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) सी-51 ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई थी।

बिना टीका वाले जरूरी काम के लिए जा सकेंगे बाहर

केरल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अकेले रह रहे, एक भी टीका न लगवाने वाले या बिना निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले लोग आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर जा सकते हैं

कोच्चि। केरल में जिन लोगों का अभी टीकाकरण नहीं हुआ है या किसी बीमारी के कारण टीके लगवाने में असमर्थ हैं तो वह अब जरूरी वस्तुओं के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। बशर्ते इन घरों में ऐसा कोई न हो, जिसे टीका लग चुका हो या उसके पास निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हो। यह जानकारी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी है।

सरकार ने जस्टिस पीबी सुरेश के समक्ष कहा कि दस अगस्त को जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, अकेले रह रहे, एक भी टीका न लगवाने वाले या बिना निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले लोग आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ता ने दवा से एलर्जी के चलते अभी कोई टीका नहीं लगवाया है। उसने अदालत में कहा कि जब तक एलर्जी रिएक्शन की जांच के लिए उसे परीक्षण खुराक नहीं दी जाती, तब तक वह

टीकाकरण नहीं करा सकता। उसने बताया कि इसके लिए वह जिला चिकित्सा अधिकारियों और निजी अस्पतालों से संपर्क साध चुका है पर परीक्षण खुराक के लिए मना कर दिया गया।

युवाओं और बच्चों में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, बंगलूरू में पांच दिन में 250 संक्रमित

बंगलूरू। कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में पिछले पांच दिनों में करीब 250 बच्चों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े बंगलूरू महानगर पालिका की ओर से जारी किए गए हैं। आंकड़े ऐसे समय पर जारी हुई हैं, जब पड़ोसी राज्य केरल में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। नगर निकाय के कोरोना बुलेटिन के मुताबिक, पांच से दस अगस्त के बीच 250 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 19 वर्ष के बीच है।

ये आंकड़े बंगलूरु में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों के अनुरूप है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई के आखिरी सप्ताह से लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जुलाई के आखिरी सप्ताह से प्रतिदिन करीब 50 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। हालांकि, वैज्ञानिक इस तथ्य के पीछे अभी तक किसी ठोस वैज्ञानिक कारण तक नहीं पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अनुमान इसलिए लगाया गया है क्योंकि, कोरोना की पिछली दोनों लहरों का ज्यादा प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ा था। लेकिन, सीरोसर्व के आंकड़ों के अनुसार युवा व बच्चे पिछली दोनों लहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं और उन्होंने इसी कारण कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। वहीं दूसरी लहर के दौरान कर्नाटक ने कई बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की थी।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंगलूरू पुलिस ने राज्य में धारा 144 को लागू कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने पिछले दिनों ही कक्षा नौ से 12 तक के स्कूलों को 23 अगस्त से खोले जाने का आदेश पारित किया है।

बंगलूरू में प्रतिदिन इस तरह सामने आए कोरोना संक्रमित

10 अगस्त
0 से 9 वर्ष - 18 संक्रमित
10 से 19 वर्ष - 27 संक्रमित

9 अगस्त
0 से 9 वर्ष - 18 संक्रमित
10 से 19 वर्ष - 24 संक्रमित

8 अगस्त
0 से 9 वर्ष - 13 संक्रमित
10 से 19 वर्ष - 25 संक्रमित

6 अगस्त
0 से 9 वर्ष - 32 संक्रमित
10 से 19 वर्ष - 34 संक्रमित

5 अगस्त
0 से 9 वर्ष - 21 संक्रमित
10 से 19 वर्ष - 38 संक्रमित

दिल्ली में सुबह-सुबह एनकाउंटर, 2 शातिर बदमाश ढेर और 2 पुलिसकर्मी हुए घायल

नई दिल्ली। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच बृहस्पतिवार सुबह-सुबह मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गए, जबकि दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश लूट समेत कई मामलों में शामिल थे और लंबे समय से दोनों की तलाश थी। जागरण संवाददाता के मुताबिक, बदमाशों की पहचान आमिर और राजमन के रूप में हुई है। आमिर लोनी का और राजमन रोहिणी का रहने वाला था। दोनों यहां एक मकान में छिपे हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को ढेर कर दिया। बदमाशों के पास से दो पिस्टल, कारतूस के साथ डेढ़ लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। आशंका है कि दोनों लूटपाट की वारदात कर यहां पहुंचे थे। जानकारी सामने आ रही है कि रोहिणी जिले की पुलिस टीम बेगमपुर से इनका पीछा करते हुए खजूरी पहुंची थी। यहां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके बाद एनकाइंटर में दोनों मारे गए।

टिल्लू गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार-दिल्ली के कराला गांव में बीते महीने गैंगवार के दौरान नितेश नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कंझावला थाना पुलिस ने सुनिल उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान हरियाणा के सोनीपत के शास्त्री पार्क निवासी अक्षय व पोस्ट आफिस पार्क निवासी सूरज उर्फ गोलू के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से पिस्टल, दो कारतूस, मोबाइल व बाइक बरामद की गई है। बदमाशों ने युवक की इसलिए हत्या की थी क्योंकि नितेश के बड़े भाई प्रवेश ने पिछले वर्ष साथियों के साथ मिलकर टिल्लू गैंग के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

किन्नौर में भूस्खलन से अब तक 13 लोगों की मौत, जिंदगी बचाने की जंग में जुटे NDRF-ITBP के जवान

शिमला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने से बड़ा हादा हो गया। किन्नौर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य को बचा लिया गया है। वहीं, 25-30 लोग अब बी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल, जिंदगी बचाने की जंग में एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी के जवान जुटे हुए हैं। दरअसल, किन्नौर जिले के निगुलसेरी में भूस्खलन वाली जगह पर सड़क साफ करने के बाद मलबे में सिर्फ रोडवेज बस की बॉडी का एक टुकड़ा मिला है। बस का और उसमें बैठे 25 यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर अंधेरा व फिर से भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बुधवार रात नौ बजे बचाव और खोजी अभियान बंद कर दिया गया। अब

गुरुवार अल सुबह से अभियान की शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि हरिद्वार जा रही हिमाचल रोडवेज की बस सतलुज नदी में गिर गई। क्योंकि, बचाव अधिकारी इसे मलबे के नीचे नहीं ढूंढ पाए। बुधवार दोपहर पहाड़ दरकने के बाद मलबे में रोडवेज बस समेत छह गाड़ियां दब गई थीं। पत्थर गिरने से एक ट्रक नदी किनारे लुढ़क गया। इसके चालक का शव बरामद कर लिया गया है। बस ड्राइवर के अनुसार, बस में 25 यात्री सवार थे। वहीं, मलबे से अब तक 13 घायलों को निकाला जा चुका है, जिनकी हालत नाजुक है। इनमें बस चालक और परिचालक शामिल हैं। जबकि 11 शव बरामद किए गए हैं। बचाव अभियान में आईटीबीपी के साथ ही सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ के जवान जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र की ओर से जारी ताजा सूचना के अनुसार, घटनास्थल पर ड्रोन से भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एक ट्रक व यात्री गाड़ी (टाटा सूमो) को मलबे से निकाल लिया गया है। टाटा सूमो में सवार आठ मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आईटीबीपी के जवानों ने बचाई जान

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसेरी में नेशनल हाईवे-5 पर हुए भूस्खलन के मलबे में फंसे एक व्यक्ति को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद जवानों ने मलबे से शख्स को जिंदा निकाला।

अंधेरा होने से बचाव व खोजी अभियान बंद-निगुलसरी में घटनास्थल पर अंधेरा व फिर से भूस्खलन के खतरे को देखते हुए रात नौ बजे बचाव और खोजी अभियान बंद कर दिया गया है। अब आज सुबह से ही बचाव टीमें राहत कार्य में जुट गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर जताई गहरी नाराजगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोगों में खाली पड़े पदों को न भरे जाने पर वीरवार को गहरी नाराजगी जताते हुए पूरे देश में उपभोक्ता आयोगों के खाली सभी पद आठ सप्ताह में भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहना होगा। इसी तरह केंद्र सरकार के मामले में उपभोक्ता मामलों के सचिव मौजूद रहेंगे।

कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश के मुताबिक रिक्त पद नहीं भरे गए तो मुख्य सचिवों को तलब करेंगे

पदों के रिक्त रहने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा न होने की ओर संकेत करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों में उम्मीद मत जगाओ, अगर उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर आप पद भर नहीं सकते तो उन्हें बनाते क्यों हैं। पद खाली रहने से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है। ये निर्देश और टिप्पणियां जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की पीठ ने दिये।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वकील आदित्य नारायण ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल सात पद हैं, जिसमें से अभी तीन पद खाली हैं। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एडीशनल सालिटिर जनरल (एएसजी) अमन लेखी से पूछा कि जब चार पद भरे जा सकते हैं तो बाकी के तीन क्यों नहीं भरे जा रहे। लेखी ने ट्रिब्युनल रिफार्म एक्ट 2021 का हवाला दिया जिसमे चेयरमैन और सदस्यों के कार्यकाल की बात की गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका नियुक्तियों से कोई लेना देना नहीं है।

- **पदों के रिक्त रहने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा न होने की ओर संकेत करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों में उम्मीद मत जगाओ, अगर उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर आप पद भर नहीं सकते तो उन्हें बनाते क्यों हैं। पद खाली रहने से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है।**

लेखी ने कहा कि वे सरकार से कहेंगे कि जल्दी पद भरें जाएं। इस पर पीठ ने कहा कि अगर आप लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते तो उनकी उम्मीदें मत जगाइये। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है। मामलों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोग चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में रिक्त पदों को राज्यों की तरह आठ सप्ताह में ही भरें।

कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रभाव, जिसमें उपभोक्ता अदालतों का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है, का अध्ययन करके चार सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करे। पीठ ने कहा कि जब लेजिस्लेटिव कमेटी ने बदलाव किये तो उस कानून का क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन होना चाहिए। यह विडंबना सभी कानूनों के साथ है कि आप कभी कानून के प्रभाव का अध्ययन नहीं करते।

न्यायमित्र वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट को राज्य उपभोक्ता आयोगों और अदालतों में खाली पड़े पदों का ब्योरा दिया। जिसके बाद कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य उपभोक्ता आयोगों के रिक्त पदों को अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर भरने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों से कहा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वे दो सप्ताह में विज्ञापन निकालें। कोर्ट ने आदेश दिया कि उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि के नियम अगर नोटीफाइ नहीं किये गये हैं तो राज्य दो सप्ताह में उन्हें नोटीफाइ करें।

अगर तय समय में रूल नोटीफाई नहीं होते तो अपने आप ही केंद्र के माडल रूल्स लागू मान लिए जाएंगे। जिन राज्यों ने सेलेक्शन कमेटी गठित नहीं की है वे चार सप्ताह में गठित करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ता अदालतों के कंप्यूटरीकरण के लिए दिये गए फंड के उपयोग पर भी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

हंगामे से हासिल

संसद सत्र का तय समय से पहले स्थगित हो जाना न केवल अफसोस, बल्कि चिंता की भी बात है। लोकसभा की बैठक बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, तो इसके लिए संसद में पैदा गतिरोध को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पेगासस जासूसी मामला, तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित अन्य कुछ मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे और सत्ता पक्ष के हठ के कारण पूरे सत्र में सदन का कामकाज प्रभावित हुआ है और सिर्फ 22 प्रतिशत काम ही हो सका। आम लोगों के मन में यह सवाल वाजिब ही उठेगा कि क्या हमने सांसदों को केवल 22 प्रतिशत काम के लिए भेजा है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद का यह व्यवहार क्या प्रशंसनीय है? भारतीय लोकतंत्र की तारीफ करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर क्या ऐसी ही तारीफ भारतीय संसद की भी हो सकती है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई, 2021 को शुरू हुई थी और इस दौरान हुई 17 बैठकों में 21 घंटे 14 मिनट ही कामकाज हुआ। उन्होंने माना कि सदन में कामकाज अपेक्षा मुताबिक नहीं रहा, तो उपाय क्या है, कौन करेगा?

राज्यसभा में भी कमाबेश ऐसी ही स्थिति रही। यह उच्च सदन है और इससे ज्यादा गंभीरता की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब ऐसे सदन के सभापति कार्यवाही का अपमान देखकर भावुक हो जाएं, तो फिर निराशा जताने के अलावा क्या रह जाता है? कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद इत्यादि पर राज्यसभा की कार्यवाही भी लगातार बाधित होती रही है। यह कैसे भुलाया जाए कि कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद सदन की मेज पर बैठ गए और कुछ सदस्य मेज पर चढ़ गए? इस पर सभापति ने कहा कि राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्रवाई का सामना करना होगा, लेकिन अब यह कैसे और कब होगा? सदन में विरोध जताना सही है, लेकिन मेज पर चढ़ जाना, मेज पर चढ़कर आसन की ओर रूल बुक फेंक देना कहां की परंपरा है? तो क्या अब समय आ गया है कि हम संसद के कामकाज को लेकर भावुक हो जाएं और आंसू बहाएं? अगर हम ऐसा करेंगे, तो दुनिया को क्या संदेश देंगे?

यह सोचना बहुत जरूरी है कि जब हम सदन में अच्छा माहौल नहीं बना सकते, तो देश में कैसे गरिमा बनाए रखेंगे? क्या भारतीय लोकतंत्र में व्यवहार का एक स्तर नहीं होना चाहिए? हंगामा करने वाले और हंगामे से लाभ उठाने वाले हर नेता को अपने गिरेबान में झांकना होगा। लोकतंत्र में सड़क पर और चुनावी मैदानों में तो संघर्ष शोभा देता है, लेकिन जब ऐसा ही राजनीतिक संघर्ष सदन में आ जाए, तो सदन का महत्व कम हो जाता है। अभी पिछले सत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति बनने लगी थी, लेकिन इस मानसून सत्र ने बेहद निराश किया है। बेशक, कोरोना पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए थी, देश की तमाम उन कमियों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के समय देश को रुला दिया, लेकिन हम चूक गए। अब देश के लोग यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब सांसद बैठें, तो दिल से महसूस करें कि देश को कहां-कहां दर्द है।

एफड़ीआई की संभावनाएं

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफड़ीआई) में इजाफे की खासी संभावनाएं हैं। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस जैसे कारोबारी अनुकूल उपायों से भारत को एफड़ीआई के माकूल गंतव्य माना जाने लगा है। अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने हाल में एक उत्साहवर्धक निष्कर्ष निकाला है। यह कि भारत पांच अरब ड़ॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है बशर्ते यहां सालाना 100 अरब ड़ॉलर की एफड़ीआई पहुंचे। अभी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2,700 अरब ड़ॉलर है। बेशक, इतनी ज्यादा मात्रा में एफड़ीआई भारत आकर्षित कर सकता है, लेकिन इससे पहले जमीनी हालात भी देख लेने होंगे। देखना पड़ेगा कि भारत में ढ़ांचागत आधार कितना मजबूत है। क्या इतना है कि विदेशी निवेशक सहज ही अपनी पूंजी भारत में लाना चाहें। सड़कों, हवाई अड्ड़ों, बंदरगाह, कंटेनर ड़िपो, गोदाम आदि से जुड़े आधार मजबूत और बेहतर होने चाहिए। देखना होगा कि ईज ऑफ डूईंग के हालात बनिस्बत बेहतर होने के बावजूद लालफीताशाही से अभी भी छुटकारा नहीं मिल सका है। सड़कें, कुछ राजमार्गों को छोड़कर, भी कोई बेहतर स्थिति में नहीं हैं। परियोजनाओं में राजनीतिक दखल भी नहीं नकारा जा सकता। कहना यह कि विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करने की स्थिति में भारत नहीं है। हालांकि कुछआर्थिक संकेतक जरूर देश में आर्थिक स्थितियों के उत्तरोत्तर सुधरने के संकेत दे रहे हैं। निर्यात के मोर्चे पर बेहद उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिकग् एक ही हफ्ते में देश के निर्यात में 50 फीसद की वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग सामानग् रत्न एवं आभूषण का निर्यात अच्छा रहने से कुल निर्यात एक से सात अगस्त के दौरान यानी मात्र एक सप्ताह में 50.48 फीसद बढ़्कर 7.41 अरब ड़ॉलर पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी से समूची दुनिया पार पाने में जुटी है। भारत इस दौरान चिकित्सा उपकरण, दवाओं और टीकों के उत्पादन में खासी बढ़त ले सकता है। भारत में टीका उत्पादन का मजबूत आधार मौजूद है। अमेरिकी संस्था ने भी ध्यान दिलाया है कि भारत बनिस्बत कम लागत पर टीकों का निर्माण करके निर्यात बढ़ा सकता है। जरूरत है कि भारत अनुकूल स्थिति और माकूल माहौल का फायदा उठाए।

कटाक्ष/सहीराम

गर्व है, कर तो लें

हालांकि अब वो वक्त नहीं रहा, जब गर्व के क्षण कभी-कभी ही आते थे। बहुत दिन तक तो हम इसी पर गर्व करते रहे कि देखो, हमने कितने देशों को कोरोना के टीके दे दिए। पर जब हमें जरूरत पड़ी तो वे हमारे पास नहीं थे। अब भी नहीं हैं। फिर भी दूसरों से लेकर हमने गर्व को शर्मसार होने से बचा लिया।

यह गर्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। वक्त थाग् तब गर्व की बड़ी राशनिंग थी। गर्व के क्षणों को हम सचमुच तरस जाते थे। राज्यवर्धन राठौड़जी एक ही मेडल लेकर आए थे और वह गोल्ड भी नहीं था, पर गर्व इतना था कि वे आज तक हमारे दुलारे बने हुए हैं। मंत्री नहीं रहे तो क्या हुआ। दुलार देना हमारा काम है, मंत्री बनाना उनका काम है, वो जानें। लेकिन अब गर्व की तरह ही मेडल भी इफरात में तो नहीं हैं, पर संतुष्ट होने लायक तो हैं ही। वरना हॉकी की हार के बाद तो पनौतियों की ऐसी लानतें दी गई थीं कि सचमुच ही डर लगने लगा था कि कहीं वही गया वक्त फिर न आ जाए। हालांकि जब टोक्यो के लिए रवाना हो रहे थे, तब तो धज ऐसी थी कि कहीं मेडलों के लिए कागाा-वागाा का ही इंतजाम न करना पडे। लेकिन फिर पनौती की लानत के बाद सचमुच डर लगने लगा। हालांकि गर्व फिर भी कम नहीं होता। एक-दो जो भी जैसा भी आताग् हम तो सारा गर्व उस पर लुटा देते। गर्व तो हमारा अपना है, उसे किसी प्रतियोगिता में जीतना तो है नहीं। पर अब मेडल जब थोड़े ज्यादा आ गए हैं, इस गर्व के बंटने का भी डर है। बेटियों पर ज्यादा गर्व करें या फौज पर जो सीमा पर हमारी रक्षा तो करती ही है, ओलंपिक में मेडल भी दिलाती है। लोग कह रहे हैं कि भैया फेंकने वाला तेज हो तो राजगद्दी भी मिल जाती है, यह तो गोल्ड मेडल है। लेकिन अब हमें इस बारे में थोडव सचेत रहना पड़ेगा कि किसानों पर कैसे गर्व किया जाए। क्योंकि मेडल लाने वालों में किसानों के बच्चे भी काफी हैं और किसान हैं कि आंदोलन से हट ही नहीं रहे। अब किसानों को मवाली और लफंगे कहकरग् बताओ किसानों के इन बच्चों की बलैया कैसे ली जाएं। लेकिन ऐसी कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिएग् जब किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही कह कर उनके फौजी बच्चों पर गर्व किया जा सकता है, तो उन्हें मवाली और लफंगा कहकर उनके खिलाड़ी बच्चों पर भी गर्व किया जा सकता है। नहीं क्या?

तस्करी का सामान नहीं भावी पीढ़ी

कैलाश सत्यार्थी

सीमा (बदला हुआ नाम) को महज 13 साल की उम्र में उनके गांव के कुछ लोगों द्वारा चुराकर दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी में बेच दिया गया था। फिर प्लेसमेंट एजेंसी से एक दंपति ने उन्हें घरेलू कामगार के रूप में केवल 20,000 रुपये में खरीद लिया। लेकिन वहां से मजदूरी के नाम पर उनको एक रुपया भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, नियोक्ताओं और ट्रैफिकर (तस्कर) द्वारा उनका बार-बार बलात्कार और शोषण किया जाता रहा। अपनी बेटी के लापता होने से निराश और घनघोर पीड़ा झेलने के बाद सीमा के मजदूर पिता हमारे पास आए। हमने सीमा को दिल्ली के एक घर में ढूंढ़ लिया। लेकिन, हमारे लिए यह हैरानी की बात थी कि गुलामी और शोषण से आजाद होने के बाद भी वह दुखी थीं और हमारे सामने नहीं आ रही थीं। पिता से मिलने के बजाय वह रोते हुए दीवार के पीछे छिप गईं। बहुत कुरेदने पर उन्होंने रोते हुए कहा, 'मैं पिता को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं अब गंदी हो चुकी हूं। मैं खुद को मार डालना चाहती हूं।' यह सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया।

यह केवल सीमा की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के सबसे गरीब, पिछड़े और हाशिये पर रहने वाले हजारों बच्चों और लड़कियों की कहानी है। दुनिया का कोई भी देश जब तक अपनी बेटियों की खरीद-फरोख्त को चुपचाप सहते जा रहा है, तब तक वह खुद को सभ्य नहीं कह सकता। किसी राष्ट्र की संपत्ति, शक्ति या प्रगति का कोई मतलब नहीं है, यदि उसके बच्चों को मध्ययुग की दास प्रथा की तरह जानवरों से भी कम कीमत में खरीदा और बेचा जाता है! चार दशक पहले 1980 में जब हमने पंजाब के सरहिंद के एक ईंट भट्टे से वर्षों से कैद वासल खान और उनकी मासूम साबो को बंधुआ मजदूरी व गुलामी से मुक्त कराकर अपना अभियान शुरू किया था, तभी हमें समझ में आ गया था कि बाल श्रम और ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) सहित तमाम सिविल सोसायटी समूहों ने मानव व्यापार के इस खतरे को समाप्त करने हेतु एक मजबूत कानून के लिए दशकों से अभियान चला रखा है। वर्ष 2017 में सीमा और उनके जैसे बाल दासता से मुक्त हजारों बच्चों और युवाओं ने इस कानून की मांग को लेकर देश के कोने-कोने में सरकारों, न्यायपालिका, धर्मगुरुओं, कॉरपोरेट घरानों, छात्रों और सिविल सोसायटी के लोगों के साथ 'भारत यात्रा' में कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। इस देशव्यापी यात्रा में 12 हजार किलोमीटर की दूरी तय की गई और 12 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। सबकी जुबान पर एक ही मांग थी कि भारत को बच्चों की खरीद-फरोख्त और शोषण रोकने के लिए एक व्यापक मानव तस्करी विरोधी कानून पारित करना चाहिए। 'भारत यात्रा' में शामिल बाल दासता और मानव व्यापार से मुक्त बहादुर नौजवानों के मन को छू लेने वाले गीत अब भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं- बिकने को तैयार नहीं हम, लुटने को तैयार नहीं हम।

> मानव व्यापार से मुक्त नौजवानों के मन को छू लेने वाले गीत अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं, बिकने को तैयार नहीं हम, लुटने को तैयार नहीं हम ।

केंद्र सरकार ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 प्रस्तावित किया है। इसे संसद

को पारित करना है। बिल का उद्देश्य अपराध के सामाजिक और आर्थिक कारणों, तस्करों को सजा, पीड़ितों की सुरक्षा व पुनर्वास सहित मानव व्यापार के सभी पहलुओं से निपटना है। यह एक व्यापक और मजबूत विधेयक है। कोविड-19 महामारी और इससे उपजी परिस्थितियों ने इस कानून की आवश्यकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने और आर्थिक संकट के चलते देश के लाखों गरीब परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन न रहने का फायदा तस्कर उठा रहे हैं। बीबीए के आंकड़े बाल तस्करी बढ़ने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। संगठन ने पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक सरकारी एजेंसियों के सहयोग से 9,000 से भी ज्यादा बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त कराया है। इसकी तुलना में महामारी से पहले 14 महीने की समान अवधि के दौरान करीब 4,700 बच्चों को मुक्त कराया गया था। ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता का एहसास कराते हैं। इसीलिए यदि हमें महामारी के प्रभाव से उबरना है, तो इसके मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए तस्करी विरोधी कानून को फौरन पारित कराने के साथ ही हमें बच्चों के लिए सालाना बजटीय आवंटन में भी वृद्धि करनी होगी। मानव व्यापार अपने आप में एक संगठित अपराध है। लेकिन यह कई अन्य अपराधों को भी जन्म देता है। यह एक समानांतर काली कमाई वाली अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, जो बाल श्रम, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरन भिक्षावृत्ति, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य अवैध व्यवसायों को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता के अलावा तस्करी के अपराध को भी भारत के संविधान के तहत दंडनीय बनाया। लिहाजा, एक मजबूत 'एंटी ट्रैफिकिंग' कानून हमारे निर्वाचित नेताओं की नैतिक और सांविधानिक जिम्मेदारी है और राष्ट्र-निर्माण और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम भी। दरअसल, बच्चों की गरीबी, मजदूरी, अशिक्षा और सुरक्षा हमारी राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं में नहीं रहे हैं। लेकिन, हमारे बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि एक पूरी पीढ़ी को बचाने के लिए इस मुद्दे को राजनीति और विकास के केंद्र में लाया जाए। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाया जाए। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसे भारत सरकार अमृतोत्सव के रूप में मना रही है। इस अवसर पर भारतमाता के लिए उसके बच्चों की आजादी से बड़ा तोहफा भला और क्या हो सकता है? हमारे नीति-निर्माता बाल तस्करी के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाकर हमारे बच्चों को आजादी, सुरक्षा व गरिमा का अमृत प्रदान कर सकते हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जातिगत जनगणना का प्रश्न

गरीब को न्याय व सम्मान हो लक्ष्य

विवेक सिंह

गरीबी की कोई जाति नहीं होती परंतु देश में जाति पर आधारित जनगणना की मांग लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाई जा रही है। जातिगत जनगणना की मांग कोई नयी नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 1947 से लगातार की जा रही है। 1951 में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने जातिगत जनगणना की मांग एक सिरे से खारिज करते हुए ऐसी जनगणना को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताया था। क्या आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं? सामाजिक न्याय और पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेक अन्य रास्ते सरकारों के पास उपलब्ध हैं फिर जातिगत जनगणना पर इतना जोर आखिर क्यों दिया जा रहा है?

जातिगत जनगणना देश की सामाजिक और राजनीतिक हालात को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होती। जातिगत जनगणना के आंकड़ों से राजनीतिक दल राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास करेंगे, पिछड़ों के विकास और सामाजिक न्याय का उद्देश्य गौण हो जायेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया, जिसमें जातिगत जनगणना की मांग की गई है। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार की मांग का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाआघाड़ी सरकार ने भी जातिगत जनगणना के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है जिसे महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का भी समर्थन है। तमिलनाडु सरकार द्वारा भी जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसने भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। 2018 में केंद्र सरकार ने भी 2021 में होने वाली जनगणना जाति आधारित हो सकती है, इस तरफ इशारा किया था, हालांकि अभी केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में पिछड़े वर्ग की गणना कराने के पक्ष में नहीं है।

भारत में जनगणना आरंभिक रूप से 1872 में शुरू हुई थी परंतु प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में हुई। इसके बाद 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से आंकड़ों को पूर्ण रूप से संकलित नहीं किया जा सका। 1931 की जनगणना अंतिम जातिगत जनगणना थी जो भाषा, धर्म और जाति पर आधारित थी। हमारे पास आज जो जातियों और उनकी संख्या (प्रतिशत) के विषय में जानकारी उपलब्ध है उसका आधार 1931 में हुई जनगणना है।

1931 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों की संख्या 15.5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) 7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की संख्या 52 प्रतिशत थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1931 के जनगणना के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से थे, देश की जनसंख्या 27 करोड़ थी जो आज 140 करोड़ है। मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना को आधार मानते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया। वर्तमान में 1931 के जनगणना के अनुसार ही ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी को 15 प्रतिशत और एसटी को 7.5 प्रतिशत (कुल 49.5 प्रतिशत) आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी हाल में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में पिछड़ों की संख्या जानने से क्या हासिल होगा।

देश की आजादी के उपरांत 1951 से लेकर 2011 तक संपन्न हुई कोई भी जनगणना जाति आधारित नहीं थी। 1951 से यह परंपरा बन गई कि जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शामिल किया जाएगा और इनकी संख्या की गणना की जाएगी। एससी और एसटी को छोड़कर किसी और जाति को जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। 2011 में यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए अलग से एक सोशियो इकोनामिक एंड कास्ट सेंसस (एसईसीसी) कराने का निर्णय लिया। एसईसीसी में 640 जिलों में आने वाले सभी 24.49 करोड़ घरों को शामिल किया गया और इस पर 4894 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। रिपोर्ट 2013 में आ भी गई परंतु आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया।

ओबीसी आरक्षण का फायदा अभी तक कुछ दर्जन जातियां ही उठा रही हैं, जबकि पिछड़े वर्ग में हजारों जातियां हैं। यदि ओबीसी में आने वाली बड़ी जातियां अपने लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के अंदर अपनी संख्या के अनुसार 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने लगीं तो उस स्थिति में सरकारों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओबीसी में आने वाली जातियां और उपजातियां हर राज्य में एक समान नहीं हैं।

संविधान निर्माताओं ने जाति रहित समाज की परिकल्पना की थी। आज जब जाति को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए उस समय जाति पर आधारित जनगणना के लिए सरकार पर राजनीतिक हित हेतु राजनीतिक दलों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जातिगत जनगणना से जाति प्रणाली को और मजबूती मिलेगी। सवर्ण सोशल माइनोरिटी में आ जाएंगे। देश में पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। ओबीसी की संख्या या प्रतिशत पता कर लेने से देश और समाज को क्या फायदा हो जाएगा? यदि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के बाद संख्या घट गई तो क्या ओबीसी को प्रदत्त आरक्षण के प्रतिशत को कम कर दिया जाएगा या ओबीसी आबादी बढ़ने की दशा में ओबीसी के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा दिया जाएगा? जातिगत जनगणना से जातिगत राजनीति नहीं बढ़ जाएगी?

आज गरीबों की संख्या की गणना किए जाने की आवश्यकता है। देश में कितने गरीब हैं इनकी संख्या का पता लगाने से केंद्र और राज्य सरकारें गरीब वर्ग को न्याय दे पाएंगी। गरीब और गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। यदि राजनीतिक दल सच में गरीब वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं तो उन्हें जातिगत जनगणना के बजाय आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उनकी संख्या की गणना के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। देश में गरीबों की गणना होनी चाहिए ताकि उनको न्याय और सम्मान मिल सके।

मुद्दा

माननीय कब होंगे हाईटेक?

ऋतुपर्ण दवे

नये संसद भवन के निर्माण की रफ्तार, माननीयों की संख्या और जनसंख्या का मौजूदा अनुपात जबरदस्त चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि निर्माणाधीन संसद के आकार, प्रकार को देखते हुए इंकार नहीं किया जा सकता कि नये तरीके से संसदीय सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया तो होनी ही है, कब होगी इस पर संदेह है। तकनीकी सवाल भी उठ रहे हैं, और व्यावहारिक कठिनाइयां भी गिनाई जा रही हैं। सांसदों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके लिए तमाम नियम, सीमाएं, जनसंख्या के अनुपात का गुणनफल भी जारी है। लेकिन उससे भी बड़े व्यावहारिक उदाहरण कई मौजूदा संसदीय क्षेत्र हैं।

दरअसल, संविधान में संशोधनों के जरिए आबादी के लिहाज से सीटों को स्थिर नहीं किया जाता तो अब तक संसदीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां काफी बदली हुई होतीं। बड़े प्रदेशों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली सरीखे राज्यों में लोक सभा सीटें बढ़ गई होतीं तो वहीं छोटे प्रदेशों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं जहां आबादी पर नियंत्रण है, वहां सीटों के घटने का नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान में 42वां संशोधन कर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक विधानसभाओं और लोक सभा की सीटों की संख्या को बढ़ने से रोक कर स्थिर कर दिया गया। 2001 में हुए 84वें संविधान संशोधन में लोक सभा और विधानसभा की सीटों में भी वर्ष 2026 तक जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों के चलते कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। इधर देश की जनसंख्या 135 करोड़ को पार करने की बातें हो रही हैं। उधर, आबादी के हिसाब से सीटों को जस का तस रखने से कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विसंगतियां भी दिखने लगीं। 1971 की जनगणना के हिसाब से हर बड़े राज्य में लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सांसद था। लेकिन अब सीटों की संख्या तो वही है जबकि जनसंख्या तेजी से बढ़ गई है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में कुछ संसदीय सीटों की आबादी 30 लाख पार कर चुकी है वहीं केरल या तमिलनाडु में सिर्फ 18 लाख की आबादी पर एक सांसद है। जाहिर है कि यह असंतुलन भी विकास में बड़ी बाधा है।

2026 में नये तरीकों से परिसीमन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ा तर्क सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही संसद की नई इमारत हैग् जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच 60 हजार स्क्वायर मीटर में त्रिकोणीय आकार में बन रही है। नई संसद में 1350 सांसद बैठ सकेंगे। राज्य सभा की नई इमारत में 400 सीट होंगी। यह संसद भविष्य के परिसीमनों की जरूरतों को लंबे समय तक पूरा करेगी। इसमें 120 दफ्तर होंगे। सांसदों, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत विशिष्ट अतिथियों के लिए छह अलग-अलग दरवाजे भी होंगे। यदि 2019 के आम चुनाव को ही आधार मान लिया जाए और 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का फॉर्मूला लगाया जाए तो देश के 88 करोड़ वोटरों के लिए 888 सांसद होने चाहिए। विसंगतियों के बीच 2026 या 2031 जब भी परिसीमन होगा, बहुत पेचीदा होगा। जाहिर है कि प्रदेश की सीमाओं, संभाग व जिलों की सीमाओं में संसदीय क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिहाज से काफी कुछ बदलने की लंबी कवायद होगी। क्षेत्रीय संतुलन, क्षेत्रीय विकास और मतदाता संख्या सारा कुछ काफी मायने रखेंगे।

यह भी ध्यान रखना होगा नई संसद अस्तित्व में आ जाएगी तब तकनीकी उड़ान में भी भारत 5 जी या उससे आगे पहुंच चुका होगा। ऐसे में अपने क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं के निराकरण के लिए दौरों की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सांसदों की हर जगह डिजिटल मौजूदगी और संसदीय क्षेत्र के हर आम व खास से खुले मंच पर सार्वजनिक संवाद की भी कोई न कोई शुरुआत हो चुकी होगी। तब आज जैसा बड़ा क्षेत्रफल या सभी से संपर्क न हो पाने जैसी बातें पुरानी हो जाएंगी। प्रतिनिधित्व में आबादी का अनुपात जरूर घटेगा लेकिन जिम्मेदारियोंग् क्षेत्रवासियों से डिजिटलाइज संपर्क व संवाद जैसी भागीदारी बढ़ेगी और इस दायित्व को जो भी माननीय कुशलता से निभा पाएंगे वही उस दौर में सच्चे जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। नई संसद में माननीयों की भी डिजिटल मोड में नई अग्नि परीक्षा से इंकार नहीं किया जा सकता। बस इंतजार है उस दिन का जब हर मतदाता सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कभी भी और कहीं भी अपने जनप्रतिनिधि से अपनी समस्याओं के लिए संवाद कर सके और उनके माननीय यह न कह सकें कि समय की कमी या दौरे में दिक्कत के चलते संसदीय क्षेत्र का विकास बाधित हुआ। यकीनन भारत जैसे विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल वाले देश के लिए यह उपलब्धि होगी।

बिड़लासॉफ्ट का शेयर अपने निवेश को कर रहा मालामाल, 1 साल में 175 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। डिजिटल एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी बिड़लासॉफ्ट ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों में पिछले 1 साल में 175 फीसदी तेजी आई है।बाजार जानकारों का कहना है कि अगले 4 से 6 महीने में इसमें और 22 फीसदी तेजी आ सकती है। इस साल यह शेयर अभी तक 64 फीसदी बढ़ चुका है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 में करीब 16 फीसदी और बीएसई 500 इंडेक्स में 20 फीसदी तेजी आई है। बिड़लासॉफ्ट कई तरह के कारोबार करने वाले सीके बिड़ला ग्रुप का हिस्सा है। इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह शेयर 16 जुलाई को 434.40 रुपये पर पहुंचा था जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। गुरुवार को बीएसई पर 3.71 फीसदी की तेजी के साथ 423 रुपये पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर 4.13 फीसदी की तेजी के साथ 425 रुपये पर बंद हुआ। पिछले कुछ महीनों से बिड़लासॉफ्ट का शेयर 375 से 420 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब इसने 420 रुपये के स्तर को पार कर लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 4 से 6 महीने में 500 रुपये तक जा सकता है जो इसके 10 अगस्त के 410 रुपये के भाव से 22 फीसदी अधिक है। कंपनी ने अगले 4 साल में 1 अरब डॉलर रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। कंपनी पर 129 करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि उसके पास 1043 करोड़ रुपये का कैश है।

सोने और चांदी में तेजी

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में 422 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का भाव 45,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत बढ़कर 1,756 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी आज बढ़त आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के दाम 113 रुपये की हल्की तेजी के साथ ही 61,314 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुए जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम बिना किसी बड़े बदलाव के 23.44 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गये।

बढ़ी हुई मांग और आधार प्रभाव ने जुलाई की घरेलू पीवी बिक्री को बढ़ाया

नई दिल्ली। कमजोर मांग के साथ-साथ आधार प्रभाव और कम ब्याज दरों ने जुलाई में साल-दर-साल और क्रमिक आधार पर भारत की घरेलू पीवी बिक्री को गति दी है। तदनुसार, यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 2,64,442 हो गई, जबकि 2020 की समान अवधि के दौरान बेची गई 1,82,779 इकाइयों की तुलना में आधिक है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्च र्स (सियाम) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि पीवी की बिक्री 2019 के 1,90,115 इकाइयों के स्तर से अधिक थी। अनुक्रमिक आधार पर भी जुलाई की बिक्री जून के दौरान बेची गई 2,31,633 इकाइयों की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा, सियाम ने कहा कि डेटा में टाटा मोटर्स जैसे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बिक्री के आंकड़े शामिल नहीं हैं। पीवी बिक्री के आंकड़ों में कार, उपयोगिता वाहन और वैन शामिल हैं।

एप्पल आईफोन कैमरों को असेंबल करने के लिए नए उपयोग करने जा रही है : रिपोर्ट

सैन फ्रांसिस्को।

टेक दिग्गज एप्पल अपने आईफोन के लिए कैमरा मॉड्यूल बनाने के तरीके में कथित तौर पर बदलाव कर रही है। इस बारे में जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वह अब प्रत्येक कैमरा लेंस को अलग-अलग बनाने का विकल्प चुन रही है। दा इलेइच की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल तक, एप्पल के आईफोन में कैमरा लेंस उसके आपूर्तिकताओं एलजी इनोटेक, शार्प और ओफिल्म द्वारा निर्मित लेंस पूर्व-इकट्ठे किए गए थे। अब, एप्पल अपने कैमरा मॉड्यूल के उत्पादन को लागत बचाने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता,फॉक्सकॉन को एक साथ कर रहा है। मैकरुमर ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि, फॉक्सकॉन ने अपने नए कैमरा असेंबली की तैयारी में दक्षिण कोरियाई फर्म हाइविजन सिस्टम से नए निरीक्षण उपकरण प्राप्त किए हैं। नई प्रणाली जांच करेगी कि क्या विस्तृत, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरों के लेंस, उनके ऑप्टिकल अक्ष और छवि सेंसर सहित, उच्च-अंत तक, आईफोन मॉडल पर सही ढंग से अलाइज हैं। गलत अलाइज के परिणामस्वरूप फोटो गुणवत्ता में भारी कमी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए बदलाव लागत बचाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये बचत ग्राहकों को दी जाएगी या नहीं। रिपोर्ट में कहा,यह भी स्पष्ट नहीं है कि नई उत्पादन पद्धति और कैमरा असेंबली में फॉक्सकॉन की भूमिका आगामी आईफोन 13 के लिए व्यवहार में होगी या नहीं। यह देखते हुए कि नए आईफोनस पहले से ही उत्पादन में हैं, ऐसा होने की संभावना नहीं है।

बीएसई ने छोटे, मध्यम पूंजी वर्ग के शेयरों में उथल-पुथल रोकने के लिए नये निगरानी उपाय किये

नयी दिल्ली,

मध्यम और लघु पूंजी श्रेणी के शेयरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के वास्ते बीएसई ने 1,000 करोड़ रुपये से कम बाजार पूंजीकरण वाले कुछ शेयरों पर नजर रखने के लिये नये निगरानी उपाय पेश किये हैं। बीएसई ने बुधवार को एक सर्कुलर में कहा कि ये नये उपाय (ऐड-ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क), 1,000 करोड़ रुपये से कम की बाजार-पूंजीकरण वाली कंपनियों पर और एक्स, एक्सटी, जेड, जेडपी, जेडवाई और वाई समूह की प्रतिभूतियों पर लागू होगा। बीएसई ने कहा कि इस संरचना के तहत छांटी गई प्रतिभूतियों में साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक मूल्य बैंड के स्थान पर छमाही, एक वर्षीय, दो साल और तीन वर्षीय मूल्य बैंड होंगे। इन प्रतिभूतियों में अतिरिक्त मूल्य दायरा उनके मौजूदा दैनिक मूल्य दायरे के अतिरिक्त होगा। जियोजित फाइनेंसियल सर्विसिज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि बीएसई की नई निगरानी व्यवस्था जिसमें कुछ खास शेयरों के लिये अतिरिक्त मूलय दायरा तय किया गया है, यह शेयर बाजार का समय पर उठाया गया कदम है। इससे इन शेयरों में अतिरिक्त सट्टेबाजी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ ने बंद पड़ी छह योजनाओं के निवेशकों को 21,000 करोड़ रुपये लौटाए

नयी दिल्ली, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड (एमएफ) ने बुधवार को कहा कि उसने बंद पड़ी छह ऋण योजनाओं के अंशधारकों को अब तक 21,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि लौटा दी है। यह राशि कंपनी की 23 अप्रैल, 2020 तक प्रबंधन अधीन संपत्ति (एयूएम) का 84 प्रतिशत है। इसी दिन कंपनी ने अपनी छह रिण वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने की घोषणा की थी। कंपनी ने बाजार में विमोचन दबाव और तरलता की कमी का हवाला देते हुये योजनाओं को बंद करने की घोषणा की थी। फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष संजय सप्रे ने निवेशकों को लिखे एक पत्र में कहा कि इसके अलावा, इस साल 31 जुलाई तक वितरण के लिए 1,111 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध थी।छह योजनाएं - फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड - में कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन संपत्ति थी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई एमएफ) द्वारा छह बंद योजनाओं के अंशधारकों को पांच चरणों में कुल 21,080 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। एसबीआई एमएफ को उच्चतम न्यायालय ने इन छह योजनाओं के लिए परिसमापक नियुक्त किया है।

डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ फाइजर वैक्सीन 42, और मॉर्डना 76 प्रतिशत प्रभावी : स्टडी

लंदन।

अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना द्वारा विकसित कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले उतने प्रभावी नहीं हैं, जितनी कि वे वायरस के मूल स्ट्रेन के खिलाफ हैं। एक नए अध्ययन से यह पता चला है। डेली मेल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका के मिनेसोटा में मेयो क्लिनिक के शोधकताओं ने पाया कि फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन जुलाई में संक्रमण के खिलाफ केवल 42 प्रतिशत प्रभावी पाई गई, जबकि मॉडर्ना वैक्सीन केवल 76 प्रतिशत प्रभावी रही। प्री-प्रिंटर सर्वर मेडरक्सिव डॉट ओआरजी पर प्रकाशित, जिसकी अभी तक समीक्षा नहीं की गई है, शोधकताओं ने अपने अध्ययन में लिखा है, कई राज्यों (मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, फ्लोरिडा और आयोवा) में मेयो क्लिनिक हेल्थ सिस्टम साइटों पर एमआरएनए -1273 (मॉडर्ना कोविड वैक्सीन) बनाम बीएनटी 162बी 2 (फाइजर कोविड वैक्सीन) के साथ पूरी तरह से टीकाकरण किए गए व्यक्तियों के बीच संक्रमण की दर की तुलना की गई तो एमआरएनए - 1273 ने बीएनटी 162बी 2 की तुलना में सफलता संक्रमण के खिलाफ दो गुना जोखिम में कमी देखी गई है। अध्ययन के लिए, टीम ने जनवरी से जुलाई तक 25,000 से अधिक मिनेसोटन पर डेटा एकत्र किया। जैसा कि दावा किया गया है, जनवरी से जून तक टीके लगभग 90 प्रतिशत प्रभावी रहे, लेकिन जून में इसमें गिरावट शुरू हुई और जुलाई में बड़े पैमाने पर गिरावट देखी गई, क्योंकि तब तक इस वैरिएंट ने अमेरिका में पकड़ बना ली थी। अध्ययन से पता चला है कि वैक्सीन प्रभावशीलता में परिवर्तन मिनेसोटा में डेल्टा वैरिएंट के प्रसार में भारी वृद्धि के साथ मेल खाता है, जो मई में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस बीच, अल्फा वैरिएंट, जो कि अमेरिका में पिछला एक प्रमुख स्ट्रेन रहा है, इसी समान समय अवधि में इसके प्रसार में 85 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक कमी देखी गई है। अमेरिका वर्तमान में डेल्टा वैरिएंट के कारण संक्रमण और मृत्यु में वृद्धि देख रहा है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, गुरुवार सुबह तक, अमेरिका में कुल मामलों और मरने वालों की संख्या क्रमशः 36,185,761 और 618,454 दर्ज की गई है। आने वाले हफ्तों में इसके और बढ़ने का अनुमान है। शोध में शामिल विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि, टीके अभी भी अस्पताल में भर्ती होने और वायरस से गंभीर मामलों को रोकने में प्रभावी हैं और दोनों के साथ अस्पताल में भर्ती होने की दर 25 प्रतिशत से कम है। पिछले महीने, फाइजर ने डेटा प्रकाशित किया था, जिसमें दिखाया गया था कि इसके टीके की प्रभावकारिता छह महीने के बाद 86 प्रतिशत तक गिर जाती है। लेकिन बूस्टर शॉट्स, जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जो कि वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और अधिक प्रतिरोधी वेरिएंट से बचाने में मदद कर सकते हैं।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी स्थिर बंद, टाटा स्टील चार प्रतिशत चढ़ा

मुंबई.

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजार बुधवार को लगभग स्थिर बंद हुए। धातु और ऊर्जा शेयरों की मजबूत मांग को बैंक और वित्तीय शेयरों में मुनाफावसूली ने बेअसर किया। बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप (मझोली और छोटी कंपनियों) शेयरों के लिये निगरानी उपाय से इस खंड में भारी बिकवाली देखी गयी। हालांकि, बाद में जब शेयर बाजार ने यह साफ किया कि केवल 1,000 करोड़ रुपये से कम बाजार पूंजीकरण वाले कुछ शेयरों के लिये ही अतिरिक्त कीमत सीमा लागू होगी, उसके बाद स्थिति सामान्य हुई। तीस शेयरों पर अधारित बीएसई सेंसेक्स में पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर लगाम लगा और यह 28.73 अंक यानी 0.05 प्रतिशत फिसलकर 54,525.93 अंक पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 2.15 अंक यानी 0.01 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 16,282.25 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में 3.86 प्रतिशत की बढ़त के साथ सर्वाधिक लाभ में टाटा स्टील का शेयर रहा। इसके अलावा एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायसं इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक में प्रमुख रूप से तेजी रही। दूसरी तरफ, गिरावट वाले शेयरों में बजाज ऑटो, सन फार्मा, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। इनमें 1.84 प्रतिशत तक की गिरावट आयी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''एशियाई तथा अमेरिकी शेयर बाजारों में कमजोर रुख के बीच बिकवाली जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार शुरूआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाये। हालांकि, बाद में सुधार आया और बाजार स्थिर बंद हुआ।'' उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियों के शेयरों के भाव में अधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर बीएसई की तरफ से किये गये उपायों से छोटी एवं मझोली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव बढ़ा। हालांकि, केवल बहुत छोटी कंपनियों तक ही पाबंदियों को लेकर उपाय सीमित रहने के बारे में स्पष्टता के बाद राहत देखी गयी। नायर ने कहा, ''प्रमुख क्षेत्रों के शेयरों में मुनाफावसूली रही। हालांकि धातु, ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में स्थिति इसके उलट रही।'' रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ''अमेरिका में 1,000 अरब डॉलर के व्यय वाला बुनियादी ढांचा विधेयक सीनेट (अमेरिका का उच्च सदन) में पारित होने के बाद मांग बढ़ने की उम्मीद से धातु शेयरों पर जोर रहा। दूसरी तरफ, औषधि, वित्तीय, वाहन और उपभोक्ता सामान से जुड़े शेयरों में बिकवाली देखी गयी...।'' एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और टोक्यो लाभ में रहे जबकि सियोल में गिरावट रही। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 70.74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर एक पैसे की हल्की गिरावट के साथ 74.44 पर लगभग स्थिर रहा। शेयर बाजार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने 178.51 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

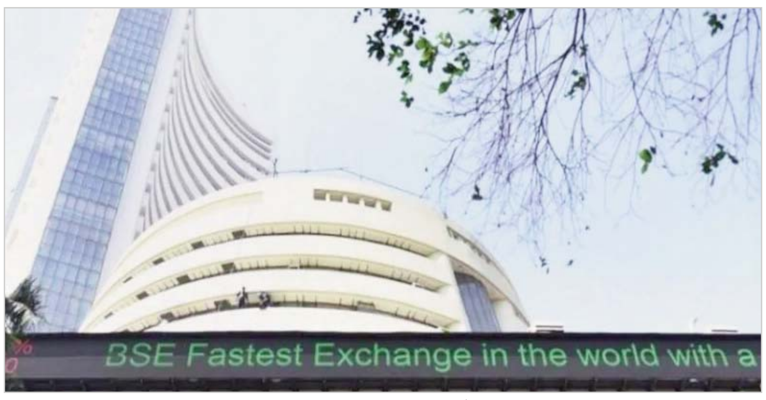

सरकार 12 से 15 लाख टन सोया खली के आयात की देगी अनुमति

नई दिल्ली :

केंद्र सरकार 12 से 15 लाख टन जीन संवर्द्धित सोया खली के आयात का आदेश देने की तैयारी में है। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने आज बताया कि सोया खली की बढ़ती कीमतों से मुर्गीपालन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसका आयात करने का निर्णय लिया है।

सोया खली का इस्तेमाल मुर्गियों के आहार (भोजन) में होता है। सोया खली के दाम बढ़ने से मवेशी आहार की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आहार में मक्का के साथ सोया खली का खास तौर पर इस्तेमाल होता है। मुर्गीपालन क्षेत्र के प्रतिनधियों ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान सोया खली की कीमतें 64 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं जिससे उनके कारोबार को चोट पहुंच रही है। सोया खली के आयात पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, %इस बारे में आधिकरिक आदेश कभी भी आ सकता है। अधिकारी ने कहा कि आयातकों को यह बताना अनिवार्य होगा कि सोया खली का इस्तेमाल केवल मवेशी के आहार के लिए होगा। अधिकारी ने कहा कि जीन संवर्द्धित सोया खली का आयात करने का निर्णय पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध एवं मत्स्य उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से लिया है। सोया खली की ऊंची कीमतों से देश का 80,000 करोड़ रुपए का मुर्गीपालन उद्योग प्रभावित हो गया है और इस कारोबार से जुड़े लोगों की कमाई पर खासा असर हुआ है। ऐसी खबर है कि इस उद्योग ने इस चुनौतीपूर्ण हालात से निकलने के लिए संबंधित मंत्रालयों से सोयाबीन की नई फसल बाजार में आने से पहले सोया खली का आयात करने की गुहार लगाई थी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि खरीफ सत्र में सोयाबीन की बुआई के दौरान सोया खली का आयात इसके उत्पादकों का उत्साह ठंडा कर सकता है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले छह महीनों से भी अधिक समय से किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मुर्गीपालन उद्योग के लोगों का कहना है कि सोया खली की आपूर्ति न के बराबर हो रही थी इसलिए इसका आयात करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है।

डिजिटल कॉइन का इस्तेमाल कर खरीद सकते हैं पिज्जा, कॉफी, आइसक्रीम

मुंबई ।

क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट यूनोकाइन ने भारतीय यूजर्स को खास तोहफा दिया है।यूनोकाइन के यूजर्स अब बिटकॉइन की मदद से पिज्जा, कॉफी, आइसक्रीम जैसे कंज्यूमर आइटम्स खरीद सकते है। इस वॉलेट की मदद से यूजर्स किसी प्रोडक्ट के लिए कैश के बजाय डिजिटल कॉइन का इस्तेमाल कर सकते। यूनोकाइन के अधिकारी ने बताया,दुनिया भर में कई बिटकॉइन यूजर क्रिप्टोकरेंसी को %बार्टर एसेट% के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। भारत में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इसकारण कंपनी ने यह तय किया है, कि इस बारे में भारतीय सब्सक्राइबर्स को भी शिक्षित किया जाए। यूनोकाइन का कहना है कि बिटकॉइन से खरीदारी की प्रक्रिया वाउचर के जरिए पूरी हो सकेगी। बिटकॉइन से यूजर पहले वाउचर खरीदे और फिर उन वाउचर से सामान खरीद सकते है। यूनोकाइन ने वाउचर खरीदने के लिए 100 से लेकर 5,000 रुपये तक की बिटकॉइन की रेंज तय की है। यूनोकाइन यूजर्स 90 ब्रैंड के लिए गिफ्ट वाउचर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डोमिनोज पिज्जा, कैफे कॉफी डे, बस्किन रॉबिन्स, हिमालया, प्रेस्टीज आदि है। क्रिप्टोकरेंसी से कंज्यूमर आइटम्स खरीदने की पेशकश केवल केवाईसी वेरिफाइड ग्राहकों के लिए मान्य होगी।यूनोकाइन एप पर लॉग इन करने के बाद यूजर को बीटीसी पेज पर जाकर %मोर% सेक्शन में %शॉप% बटन पर क्लिक करना होगा। यहां उन ब्रैंड की जानकारी होगी, जिनके लिए वाउचर खरीदे जा सकते हैं। जिस ब्रैंड से खरीदारी करनी है,उस चुनने के बाद यूनोकाइन एप पर वाउचर रुपये मूल्य में दिखाई देने वाले है। वाउचर खरीदने पर उसकी राशि यूजर के क्रिप्टो वॉलेट से बिटकॉइन के तौर पर काटी जाएगी। इसके बाद यूजर को वाउचर कोड भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल कंज्यूमर आइटम्स को खरीदने में हो सकेगा। इन ई-वाउचर्स को गिफ्ट भी किया जा सकता है।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की 35,000 करोड़ रुपये की रिण पूंजी जुटाने की योजना

नयी दिल्ली,

कार्लाइल समूह सौदे में कानूनी बाधाओं का सामना कर रही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अब 35,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने पर विचार कर रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने बुधवार को एक नियामक सूचना में कहा, कंपनी तीन सितंबर, 2021 को अपनी वार्षिक आम सभा (एजीएम) में शेयरधारकों से इस पर मंजूरी मांगेगी। कंपनी ने कहा कि वह रिण इश्यू के जरिए और वित्त जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। नियामकीय सूचना के मुताबिक, ÷33वीं एजीएम में ऋण जारी करने के माध्यम से और धन जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जा रही है और शेयरधारकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे निदेशक मंडल को एक या एक से अधिक किश्तों में कुल 35,000 करोड़ रुपये के प्रतिदेय, सुरक्षित / असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की समय-समय पर पेशकश करने के लिए अधिकृत करें।

सोमवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कंपनी के मौजूदा निवेशक कार्लाइल ग्रुप के नेतृत्व में 4,000 करोड़ रुपये के इक्विटी फंड इन्फ्यूजन और अन्य शेयरों एवं वारंटों के तरजीही आवंटन से संबंधित मामले में अदालत में कंपनी की याचिका पर एक खंडित फैसला दिया। अगर सौदा नियामकीय और कानूनी बाधाओं में नहीं फंसता, तो कंपनी इक्विटी पूंजी जुटाने में सफल रहती।

माल निर्यात के 2028 तक एक खरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद : सचिव

बिजनेस डेस्क।

देश से माल का निर्यात वर्ष 2027-28 तक 1,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है और सरकार ने इस आंकड़े को हासिल करने के लिए रूप रेखा भी तय कर ली है। वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बुधवार को यह बात कही। वाणिज्य मंत्रालय चालू वित्तीय वर्ष में 419 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस लक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर पर 31 वस्तुओं, क्षेत्र और राज्यों के स्तर पर बांटा गया है। सचिव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय निर्यात लगभग 290 अरब डॉलर से 330 अरब डॉलर के बीच ऊपर-नीचे होता रहा है। सुब्रह्मण्यम ने उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''हमने 500 अरब डॉलर निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए वास्तव में एक रूप रेखा तय कर ली है। एक खरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को किस तरह प्राप्त किया जाए, उस पर भी काम कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इसके अलावा सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने को लेकर भी काम जारी है। वर्ष 2027-28 तक सेवा क्षेत्र के निर्यात का 700 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। सचिव ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे क़दमों के बारे में बताते हुए कहा कि निर्यात प्रोत्साहन योजना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) अब बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर (आरओडीटीईपी) दरों में छूट को लेकर शुक्रवार तक जानकारी देगी।

उन्होंने कहा कि इसी तरह वस्त्रों के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्क योजना (आरओएससीटीएल) के तहत दी जानी वाली छूट को एक या दो दिन में अधिसूचित कर दिया जाएगा। इससे निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईपीएल के टीवी, डिजिटल और मीडिया राइट्स के लिए रिलायंस भी दावेदार

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टीवी,डिजिटल और मीडिया राइट्स बेचने के लिए टेंडरों निकाला है। मीडिया राइट्स की दौड़ में इस बार रिलायंस भी बड़ी दावेदार मानी जा रही है। वर्तमान में बीसीसीआई का चार साल का अनुबंध स्टार के साथ है। यह अनुबंध साल 2022 में समाप्त होगा। इसी को देखते हुए रिलायंस मीडिया राइट्स हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। आईपीएल के प्रशंसकों की तदाद करोड़ों में है और वह दुनिया भर में फैले हैं। ऐसे में रिलायंस के अलावा स्टार इंडिया, सोनी पिक्चर और ऐमेजॉन भी राइट्स की दौड़ में बनी हुई हैं। दिग्गज कंपनियों के आने से इस बार आईपीएल के टीवी-डिजिटल, मीडिया राइट्स के लिए बड़ी बोली लगने के आसार हैं। गौरतलब है कि आईपीएल के टीवी, डिजिटल और मीडिया राइट्स के लिए पिछली बार करीब 24 कंपनियां दौड़ में थीं। तब इनमें से सबसे आगे स्टार इंडिया रही थी। रिलायंस ने पिछली बार ज्यादा रुचि नहीं दिखायी थी पर इस बार वह टीवी, डिजिटल और मीडिया प्रसारण अधिकारों के लिए बड़ी रकम लगा सकती है। रिलायंस की टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है

उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को किया सम्मानित, बनाया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ब्रांड एंबेसडर

देहरादून ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाडी वंदना कटारिया को टोक्यो ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। इस बीच एक मैच में वह हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाडी भी बनी। भारतीय महिला टीम कांस्य पदक के करीबी मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से हारने के कारण टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। वंदना के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद क्षेत्र में स्थित आवास में पहुंचे धामी ने उन्हें उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में स्त्री सशक्तिकरण के लिए दिए जाने वाले तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया और इसके तहत उन्हें 31 हजार रू का चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वंदना कटारिया को प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग के तहत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। धामी ने कहा कि वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से देश के साथ ही प्रदेश का भी मान-सम्मान बढ़ाया है तथा एक मैच हैट्रिक करके अपनी अलग पहचान बनाई। धामी ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत और यतीश्वरानंद तथा हरिद्वार जिले से विधायक आदेश चौहान और देशराज कर्णवाल भी मौजूद थे। टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को महिला हॉकी पूल 'ए' के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फारवर्ड वंदना ने एक के बाद एक तीन गोल करके हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया था।

भारत के खिलाफ हुई हालिया सीरीज से श्रीलंका क्रिकेट को हुई मोटी कमाई

कोलंबो।

भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में हुई सीमित ओवरों की सीरीज से श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को बड़ी रकम मिली है। कुणाल पांड्या के कोरोना की चपेट में आने के बाद भी टी20 मैचों के साथ दौरा पूरा हुआ। भारत ने वनडे सीरी 2-1 से जीती जबकि श्रीलंका ने समान अंतर से टी20 सीरीज जीती। इसके सचिव मोहन डी सिल्वा ने कहा कि तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने से एसएलसी को 1.45 करोड़ डॉलर (107 करोड़ रुपये) का राजस्व प्राप्त हुआ है। डेली एफटी द्वारा डी सिल्वा के हवाले से कहा है, एफटीपी (भविष्य के दौरे कार्यक्रम) के अनुसार यह दौरा केवल तीन वनडे मैचों के लिए था, लेकिन हमारे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) को हमें अतिरिक्त तीन टी20 देने के लिए मनाने में कामयाब रहे, जिसके परिणामस्वरूप हमें फायदा हुआ। यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारे संबंधों के कारण संभव हुआ। हमें प्रसारण और अन्य अधिकारों जैसे मैदान, आदि से 1.45 करोड़ डॉलर मिले। डी सिल्वा ने कोविड -19 मामले के बावजूद दौरे को पूरा करने के लिए बीसीसीआई और भारतीय टीम को भी धन्यवाद दिया। श्रीलंका अब तीन वनडे और तीन टी20 मैचों के लिए 2-14 सितंबर तक दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा।

पैर की चोट के कारण सिनसिनाटी टूर्नामेंट से भी हटे नडाल

सिनसिनाटी : टोरंटो में चल रहे हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट से हटने के बाद दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रफेल नडाल ने कहा है कि वह बायें पैर में चोट के कारण सिनसिनाटी में होने वाली आगामी टेनिस प्रतियोगिता से भी हट रहे हैं। नडाल पिछले कुछ समय से पैर की चोट से परेशान हैं। सिनसिनाटी टूर्नामेंट से हटने के बाद 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता नडाल के अमेरिकी ओपन से पहले किसी टूर्नामेंट में खेलने की संभावना नहीं है। नडाल जब 2019 में पिछली बार अमेरिकी ओपन में खेले थे तो उन्होंने खिताब जीता था। एड़ी की चोट से परेशान मिलोस राओनिक ने भी बुधवार को सिनसिनाटी टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इसके अलावा रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और सोफिया केनिन जैसे स्टार खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे। पैंतीस साल के नडाल पिछले हफ्ते वाशिंगटन में खेले थे। उन्होंने तीन सेट में जैक सॉक को हराया था लेकिन लॉयड हैरिस के खिलाफ तीन सेट में हार गए थे। इन दोनों ही मुकाबलों में नडाल पैर की चोट से परेशान दिख रहे थे।

मेरा सपना है एक बार फिर चैंपियंस लीग जीतने का : मेसी

पेरिस।

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने बुधवार को कहा कि वह अपनी नई टीम पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के साथ चैंपियंस लीग जीतने का सपना देख रहें हैं।

34 वर्षीय मेसी ने अपनी पूर्व टीम बार्सिलोना के साथ चार चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं। मेसी ने बार्सिलोना के साथ आखिरी चैंपियंस लीग खिताब 2015 में जीता था। पीएसजी अभी भी अपने पहले खिताब के खोज में है। 2020 के उसे फाइनल में बायर्न म्यूनिख से हार का सामना करना पड़ा था। पार्क दे प्रिंसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेसी ने कहा, मेरा लक्ष्य और मेरा सपना है कि मैं एक बार फिर चैंपियंस लीग जीतूं। मुझे लगता है कि हमारे पास इसे करने के लिए टीम है। मेसी ने पीएसजी के साथ दो साल का करार किया है, और अगर वे चाहें तो एक साल और बढ़ा सकते हैं। मेसी जल्द ही पीएसजी के लिए पहला मैच खेलते नज़र आ सकते हैं। लीग 1 में इस रविवार को पीएसजी अपने घरेलू मैदान पर स्ट्रासबर्ग से खेल रहा है। मेस्सी ने एक बार फिर नेमार के साथ टीम बनाने के मौके के बारे में भी बताया। यह जोड़ी 2013 और 2017 के बीच बार्सिलोना के लिए एक साथ दिखाई दी थी। पीएसजी में इस जोड़ी के साथ फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे भी शामिल हैं, जिनका क्लब के साथ एक साल का अनुबंध शेष है। मेसी ने कहा, एमबाप्पे और नेमार के साथ खेलने के लिए मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं। नेमार और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ और अपने सभी साथियों के साथ टीम को और मजबूत करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

टेनिस - टियाफो ने टोरंटो में शापोवालोव को हराया

टोरंटो। अमेरिका के फ्रांसेस टियाफो ने कनाडा के टोरंटो में जारी नेशनल बैंक ओपन में स्थानीय स्टार डेनिस शापोवालोव को सीधे सेटों में हराकर अपना विजयक्रम जारी रखा है। 23 वर्षीय अमेरिकी ने बुधवार शाम को अपने दूसरे दौर के मैच में शापोवालोव को 6-1, 6-4 से हराया। दुनिया में 52वें स्थान पर काबिज टियाफो ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस मैच में ब्रेकप्वाइंट का सामना नहीं किया। शापोवालोव ने हवा की परिस्थितियों में संघर्ष किया और टियाफो को अपनी सर्विस के साथ संघर्ष करते हुए मैच को अपने नियंत्रण लेने की अनुमति दी। फ्रांस के गेल मोनफिल्स ने ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन को 3-6, 6-3, 6-4 से हराया जबकि रूस के एंड्री रुबलेव ने इटली के फैबियो फोगनिनी को 7-6 (4), 6-3 से हराया। इसी तरह पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्काक्स जापान के केई निशिकोरी के अपने मुकाबले से हटने के बाद आगे बढ़े। एक अन्य मैच में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन ने फ्रांस के बेनोइट पायर को 7-5, 6-1 से हराया जबकि अमेरिका के जॉन इस्नर ने चिली के क्रिस्टियन कैरिन को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय महिला टीम के बदले जाएंगे कोच और ट्रेनर

नई दिल्ली - भारतीय महिला क्रिकेट टीम के क्षेत्ररक्षण कोच अभय शर्मा ने आस्ट्रेलिया दौरे से पहले बेंगलुरू में जैव सुरक्षित वातावरण (बायो बबल) में प्रवेश नहीं किया है तथा उनका और ट्रेनर नरेश रामदास का बदला जाना तय है। अभय शर्मा की इंग्लैंड दौरे में खिलाड़ियों ने भी प्रशंसा की थी लेकिन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के सहयोगी स्टाफ शामिल इस पूर्व क्रिकेटर ने मंगलवार की शाम को बायो बबल में प्रवेश नहीं किया जिससे खिलाड़ी भी हैरान हैं। ब्रिटेन दौरे पर गये सहयोगी स्टाफ में से पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिवसुंदर दास ने अपना पद बरकरार रखा है जबकि मुख्य कोच रमेश पोवार गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि नए क्षेत्ररक्षण कोच और ट्रेनर के नामों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। शर्मा ब्रिटेन दौरे से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान भी टीम के क्षेत्ररक्षण कोच थे।

बोउमोस और कौको क्लब में अहम भूमिका निभाएंगे: एटीके मुख्य कोच हबास

कोलकाता।

एटीके मोहन बागान के मुख्य कोच एंटोनियो लोपेज हबास को लगता है कि उनके दो नए विदेशी खिलाड़ी- ह्यूगो बोउमोस और जोनी कौको, आगामी एएफसी कप के साथ-साथ इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में उनके के लिए कारगर साबित हो सकते हैं।

पिछले सीजन में मुंबई सिटी एफसी के लिए आईएसएल ट्रॉफी जीतने के बाद अब बोउमोस एटीके मोहन बागान से जुड़ गए हैं और फिनलैंड के यूरो कप 2020 के बाहर हो जाने के बाद कौको ने क्लब के साथ करार किया है। हबास ने कहा कि, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। बोउमोस आईएसएल में हमारे लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होंगे। जोनी कौको भी हमारे लिए अहम खिलाड़ी हैं क्योंकि उनके पास डिफेंस और अटैक के बीच अच्छा का संतुलन है। ये दोनों विदेशी खिलाड़ी अगले सीजन के लिए हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। एटीके मोहन बागान ने इस साल की शुरूआत में मार्च में मुंबई सिटी एफसी से 2020/21 आईएसएल फाइनल हारने के बाद से सात नए खिलाड़ियों को क्लब में शामिल किया हैं - बोउमोस, कौको, लिस्टन कोलाको, अमरिंदर सिंह, दीपक टांगरी, आशुतोष मेहता और विद्यानंद सिंह, और अब कोच को आने वाले मैचों के लिए एक नई टीम बनानी होगी। हबास ने आगे कहा कि, मेरा यही मानना है कि अब हमें हर दिन मेहनत करना होगा और प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करनी होगी। हमें एक नई टीम बनानी होगी क्योंकि हमने टीम में बहुत सारे बदलाव किए हैं। मैदान पर सर्वश्रेष्ठ र्पदशन करने के लिए हर दिन हम हर दिन प्रैक्टिस कर रहें हैं। एटीके मोहन बागान 18 अगस्त को अपने पहले मैच में, बेंगलुरु एफसी और क्लब ईगल्स (मालदीव) के बीच प्ले-ऑफ टाई के विजेता से भिड़ेंगे। अपने बाकी के दो ग्रुप मैचों में, वे 21 अगस्त को माज़िया स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन (मालदीव) और 24 अगस्त को बशुंधरा किंग्स (बांग्लादेश) के खिलाफ खेलेंगे।

ओलम्पिक चैम्पियन चोपड़ा विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे

मुंबई।

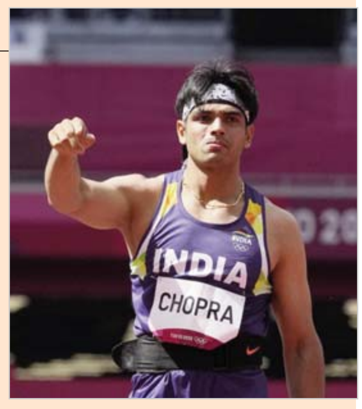

टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक ने भारत के नीरज चोपड़ा को हर बुधवार को अपडेट होने वाली नवीनतम विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में 14 स्थान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। चोपड़ा, जिन्होंने शनिवार को टोक्यो में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीता था, जर्मनी के जोहान्स वेटर से 1395 अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं। 1396 अंकों के साथ शीर्ष क्रम के जर्मन वेटर टोक्यो में फाइनल में विफल रहे और नौवें स्थान पर रहे। पोलैंड के मार्सिन क्रुकोवस्की 1302 अंकों के साथ तीसरे जबकि टोक्यो में रजत पदक जीतने वाले चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज 1298 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर 1291 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। चोपड़ा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ओलंपिक की शुरूआत से पहले, चोपड़ा ने कहा था कि यह उस दिन का प्रदर्शन है जो विश्व रैंकिंग से अधिक मायने रखता है। वह रैंकिंग में उच्च पदों पर काबिज लोगों से आगे स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित करने गए। चोपड़ा फिलहाल ब्रेक पर हैं और सकर्ट में वापसी पर डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद करेंगे। उन्होंने ओलंपिक से पहले विदेश में चार स्पर्धाओं में हिस्सा लिया थाष इस साल मार्च में पटियाला में 88.07 मीटर की दूरी के साथ उन्होंने अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। चोपड़ा के लिए अब लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में भाला फेंक में प्रमुख बल के रूप में अपनी जगह पक्की करने के लिए 90 मीटर का आंकड़ा पार करना है।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग : बुमराह ने शीर्ष-10 में बनाई जगह

लंदन । भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में शीर्ष-10 में जगह बना ली है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नौ विकेट लिए थे जिसके दम पर उन्होंने 10 स्पॉट की छलांग लगाकर 760 रेटिंग अंकों के साथ नौवें स्थान पर जगह बनाई। बुमराह जो सिंतबर 2019 में अपने करियर के सर्वाधिक तीसरे नंबर पर थे उन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद 77 अंक हासिल किए। मार्च के बाद यह पहली बार है जब बुमराह ने शीर्ष-10 में जगह बनाई है। बुमराह के अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड (आठवें) और मिशेल स्टार्क (10वें) स्थान पर हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन रैंकिंग में सातवें स्थान पर हैं। ओली रॉबिंसन 22 स्थान के सुधार के साथ 46वें और भारत के शार्दुल ठाकुर 19वें स्थान की उछाल के साथ 55वें नंबर पर मौजूद हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं। रूट ने पहले मैच में 64 और 109 रन बनाए थे जिसकी मदद से उन्हें 49 रेटिंग अंक हासिल हुए। कोहली पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं।

टोक्यो में निशानेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद तीन भाग में होगी समीक्षा

नई दिल्ली ।

तोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद तीन भाग में समीक्षा की जाएगी और भारतीय निशानेबाजी महासंघ (एनआरएआई) के अधिकारियों के प्रदर्शन का भी विश्लेषण होगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) से जुड़े एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि तीन भाग की समीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। रियो ओलंपिक से खाली हाथ लौटने के बाद भारतीय निशानेबाज तोक्यो ओलंपिक से भी बिना पदक के लौटे। सूत्र ने गुरुवार को बताया, 'समीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है और यह तीन हिस्सों में होगी। सबसे पहले खिलाड़ी, फिर कोच और सहयोगी स्टाफ और फिर राष्ट्रीय महासंघ के अधिकारियों की समीक्षा होगी।'' यह पूछने पर कि क्या एनआरएआई अध्यक्ष रनिंदर सिंह का भी विश्लेषण होगा, सूत्र ने इसका सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि महासंघ के प्रमुख इसके लिए तैयार हैं और तोक्यो में खेलों के दौरान भी उन्होंने इसी तरह की बात कही थी। सूत्र ने कहा, 'कोई सही ख्याति वाला व्यक्ति महासंघ के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। वह इन चीजों को देखेगा कि जहां तक ओलंपिक की तैयारी का सवाल है तो महासंघ ने कहां कमी छोड़ी।' उन्होंने कहा, 'इस समीक्षा में महासंघ को अलग नहीं रखा जाएगा।' महासंघ के शीर्ष पदाधिकारियों के विश्लेषण से पहले एनआरएआई निशानेबाजों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की समीक्षा करा रहा है। तोक्यो में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय महासंघ की नजरें ढांचे में बड़े बदलावों पर है। एक अधिकारी ने कहा, 'निश्चित तौर पर आप पूरे ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं और यह सिर्फ कोचों तक सीमित नहीं होगा। सभी का विस्तार से आकलन होगा क्योंकि तोक्यो में विफलता के पीछे के कारण ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।' उन्होंने कहा, 'निशानेबाजों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की समीक्षा एनआरएआई अध्यक्ष, सचिव (राजीव भाटिया) और महासचिव (डीवी सीताराम राव) करेंगे।' टोक्यो अभियान के दौरान विवादों की कहानियां भी सामने आई जब युवा स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर और उनके पूर्व कोच जसपाल राणा के बीच मतभेद की खबरों ने सुर्खियां बटोरी।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का गुवाहाटी में भव्य स्वागत

गुवाहाटी । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां गुरुवार को ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का हवाई अड्डे पहुंचने पर शानदार स्वागत किया। इसके बाद उन्हें दोपहर को राज्य सरकार की ओर से आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व के साथ गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हमारी स्टार ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का स्वागत कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपनी सफलता के साथ एक अरब सपनों को प्रज्वलित किया है और विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने की ख्वाहिश रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। लवलीना शाम को राज्यपाल जगदीश मुखी से भी मिलेंगी और बाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली लौटेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक पदक विजेताओं से मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में महिला वेल्टरवेट (69 किग्रा) मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूखी आंखें, डिजिटल स्क्रीन स्ट्रेन, परिपक्व मोतियाबिंद के बढ़ रहे हैं मामले

महामारी के दौरान सूखी आंखों और डिजिटल आंखों में खिंचाव के मामलों की संख्या बढ़ गई है। डिजिटल आई स्ट्रेन और सूखी आंखों के मामलों में प्रकाश–उत्सर्जक डिजिटल स्क्रीन के अत्यधिक संपर्क के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, क्योंकि लोग घर से काम करने और घर से अध्ययन करने के परिवश्यों के अनुकूल थे। उनके अनुसार, परिपक्व मोतियाबिंद के मामले 2019 की अंतिम तिमाही में कुल मोतियाबिंद मामलों के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में इसी अवधि के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक हो गए। 2020 में किए गए एक आंतरिक अध्ययन का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि महामारी की पहली लहर के दौरान चिकित्सा हस्तक्षेप की मांग में देरी – लॉकडाउन प्रतिबंधों या संक्रमण के जोखिम के डर के कारण, कई रोगियों की आंखों की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। इसलिए, किसी भी आंख की समस्या को नजरअंदाज किए बिना, रोगियों को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। रोगियों और जनता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखें और बिना किसी देरी के चिकित्सा हस्तक्षेप की तलाश करें, क्योंकि कोविड – 19 और जीवनशैली में बदलाव, विशेष रूप से स्क्रीन समय में वृद्धि, आंखों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है।

आयुर्वेद में दी जाती है मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने की सलाह

मिट्टी के बर्तन में खाने क स्वाद अलग ही आता है। हालांकि अब शहरों में लोगों द्वारा मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं होता है। मिट्टी के बर्तन में खाने के स्वाद का पता आप कुल्हड़ वाली चाय से लगा सकते हैं। चाय को आप कप में पिएं तो अलग स्वाद आएगा और यदि वही चाय आप कुल्हड़ में पिएंगे तो स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे में अगर पूरा खाना ही मिट्टी के बर्तनों में बने तो स्वाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हांडी में खाना बनाने के कई फायदे हैं। आयुर्वेद द्वारा मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे।

- अगर आप कम तेल में खाना पकाना चाहते हैं, तो हांडी में खाना पकाना अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी पसंद का खाना इसमें मात्र 1 चम्मच तेल के साथ आराम से पका सकते हैं। ये स्लो कुकिंग प्रोसेस है, जो नैचुरली तेल छोड़ता है। ऐसे में खाना स्वादिष्ट और हेल्दी बनता है।
- मिट्टी प्राकृतिक रूप से क्षारीय प्रकृति की होती है। गर्म होने पर मिट्टी भोजन में मौजूद एसिड के साथ परस्पर क्रिया करती है, ये पीएच स्तर को न्यूट्रलाइज करती है और भोजन को पचाने में आसान बनाती है।
- मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से सभी न्यूट्रिएंट्स खाने में शामिल हो जाते हैं जो इसके स्वाद को बढ़ा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन में बने खानमे में कैलशियम, फोस्फोरस, आइरन, मेग्निशियम और सल्फर मिलता है, जो खाने को बहुत हेल्दी बना देता है।
- स्टील और नॉन स्टिक के मुकाबले, मिट्टी की हांडी सस्ती आती है। ये आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाती है। ऐसे में जब आप इन्हें खरीदें, तो अच्छे से चेक करें कि इसमें कहीं कोई छेद या फिर क्रैक तो नहीं है।

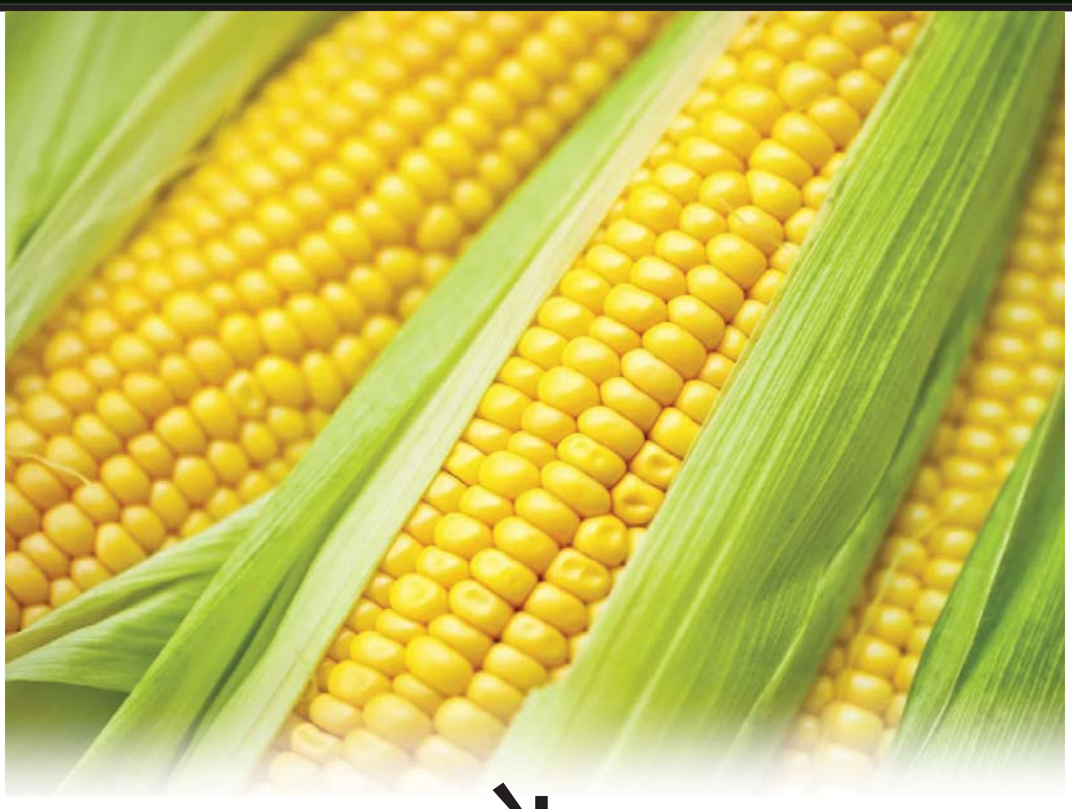

भुट्टा कहें या मक्का स्वाद के साथ सेहत के फायदे

झमाझम बरसात का मौसम आ गया है। रिमझिम बारिश में भुट्टा न खाया जाए, ऐसा संभव ही नहीं.सिके हुए देशी भुट्टे हों या फिर स्टीम में पके अमेरिकन कॉर्नद़ोनों का अपना ही मजा है। स्वाद तो इनका मजेदार होता ही है, जानिए सेहत के फायदे भी

- सबसे पहली बात तो यह है कि बड़ों को साथ–साथ बच्चों को भी भुट्टे अवश्य खिलाने चाहिए इससे उनके दांत मजबूत होते हैं।
- दूसरी बात कि जब आप भुट्टे खाएं तो दानों को खाने के बाद जो भुट्टे का भाग बचता है उसे फेंकें नहीं बल्कि उसे बीच से तोड़ लें और उसे सूंघें। इससे जुकाम में बड़ा फायदा मिलता है। बाद में इसे जानवर को खाने के लिए डाल सकते हैं।
- अगर आप इसे जानवर को नहीं देते हैं तो उन्हें सूखाकर रखें फिर इन्हें जलाकर राख बना कर रख लें। सांस के रोगों में यह बड़ा कारगर इलाज है। इस राख को प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ फांकने से खांसी का इलाज होता है। खांसी कैसी भी हो यह चूर्ण लाभ देता ही है। यहां तक कि कुकर खांसी में भी बड़ी राहत मिलती है।
- आयुर्वेद के अनुसार भुट्टा तृप्तिदायक, वातकारक, कफ, पित्तनाशक, मधुर और रुचि उत्पादक अनाज है। इसकी खासियत यह है कि पकाने के बाद इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। पके हुए भुट्टे में पाया जाने वाला कैरोटीनायड विटामिन–ए का अच्छा स्रोत होता है।
- भुट्टे को पकाने के बाद उसके 50 प्रतिशत एंटी–ऑक्सीअडेंट्स बढ़ जाते हैं। यह बढती उम्र को रोकता है और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। पके हुए भुट्टे में फोलिक एसिड होता है जो कि कैंसर जैसी बीमारी में लड़ने में बहुत मददगार होता है।
- इसके अलावा भुट्टे में मिनरल्स और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भुट्टे को एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है, जो दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है।
- बच्चों के विकास के लिए भुट्टा बहुत फायदेमंद माना जाता है। ताजे दूधिया (जो कि पूरी तरह से पका न हो) मक्का के दाने पीसकर एक खाली शीशी में भरकर उसे धूप में रखिए। जब उसका दूध सूख कर उड़ जाए और शीशी में केवल तेल रह जाए तो उसे छान लीजिए। इस तेल को बच्चों के पैरों में मालिश कीजिए। इससे बच्चों का पैर ज्यादा मजबूत होगा और बच्चा जल्दी चलने लगेगा।
- इस तेल को पीने से शरीर शक्तिशाली होता है। हर रोज एक चम्मच तेल को चीनी के बने शर्बत में मिलाकर पीने से बल बढ़ता है। ताजा मक्का के भुट्टे को पानी में उबालकर उस पानी को छानकर मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब की जलन व गुर्दों की कमजोरी समाप्त हो जाती है।
- टीबी के मरीजों के लिए मक्का बहुत फायदेमंद है। टीबी के मरीजों को या जिन्हें टीबी होने की आशंका हो हर रोज मक्के की रोटी खाना चाहिए। इससे टीबी के इलाज में फायदा होगा।
- मक्के के बाल (सिल्क) का उपयोग पथरी रोगों की चिकित्सा मे होता है। पथरी से बचाव के लिए रात भर सिल्क को पानी मे भिगोकर सुबह सिल्क हटाकर पानी पीने से लाभ होता है। पथरी के उपचार में सिल्क को पानी में उबालकर बनाये गये काढ़े का प्रयोग होता है।
- यदि गेहूं के आटे के स्थान पर मक्के के आटे का प्रयोग करें तो यह लीवर के लिए अधिक लाभकारी है। यह प्रचूर मात्रा में रेशे से भरा हुआ है इसलिए इसे खाने से पेट अच्छा रहता है। इससे कब्ज, बवासीर और पेट के कैंसर के होने की संभावना दूर होती है।
- भुट्टे के पीले दानों में बहुत सारा मैगनीशियम, आयरन, कॉपर और फॉस्फोरस पाया जाता है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। एनीमिया को दूर करने के लिए भुट्टा खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन बी और फोलिक एसिड होता है।
- खुजली के लिए भी भुट्टे का स्टॉर्च प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके सौंदर्य लाभ भी कुछ कम नहीं है। इसके स्टार्च के प्रयोग से त्वचा खूबसूरत और चिकनी बन जाती है।
- भुट्टा दिल की बीमारी को भी दूर करने में सहायक है क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैरोटिनॉइड और बायोफ्लेवनॉइड पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से बचाता है और शरीर में खून के प्रवाह को भी बढ़ाता है।
- इसका सेवन प्रेगनेंसी में भी बहुत लाभदायक होता है इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसे अपने आहार में जरुर शामिल करना चाहिए। क्योंकि इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है जो गर्भवती के लिए बेहद जरूरी है।

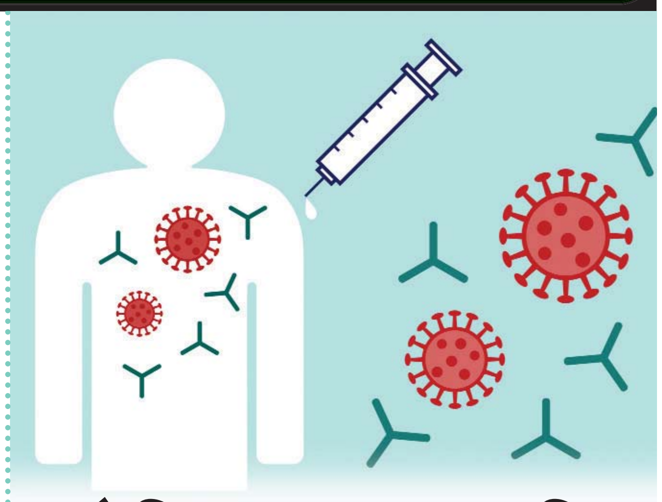

कोविड–19 संक्रमित होने के कितने दिनों तक शरीर में रहती है एंटीबॉडी

सार्स कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है ताकि इस बीमारी की चपेट में नहीं आएं। अगर कोई संक्रमित हो भी जाता है तो वह जल्द ठीक होने की आकांशा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं कुछ मरीज होम आइसोलेशन में रहकर भी ठीक हो रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हालांकि अभी भी बहुत से लोगों में कोविड-19 के टीके को लेकर मन में डर है। क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स का डर बैठ गया है। विशेषज्ञ, सरकार और डॉक्टर द्वारा यही अपील की जा रही है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के बाद वैक्सीनेशन ही बचाव का उपाय है। वहीं अगस्त-सितंबर तक तीसरी लहर की भारत में संभावना जताई जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत से बाहर अन्य देशों में तीसरी लहर को घोषित कर दिया गया है। अभी तक भारत में 4 से सवा चार करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है।

जिन्हें कोविड वैक्सीन लग चुकी है उनके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरी के पहले तीसरा डोज लागने से कोविड नहीं होगा। और अगर मई में ही दोनों वैक्सीन के डोज लग गए है तो क्या अगस्त –सितंबर तक वैक्सीन का प्रभाव कम तो नहीं हो जाएगा। हाल ही में एक रिसर्च में खुलासा भी हुआ है कि कोविड संक्रमित होने के बाद आपकी बॉडी में पैदा हुई एंटीबॉडी का असरदार कब तक रहेगा।

9 महीने तक रहेगी एंटीबॉडी

इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ और ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन के रिसर्चर द्वारा शोध में किया गया। इसमें सामने आया कोविड से संक्रमित होने के बाद शरीर में करीब 9 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रहती है। रिसर्च के अनुसार अगर व्यक्ति में लक्षण दिखे हो या नहीं संक्रमित होने पर 9 महीने तक एंटीबॉडी रहेगी। हालांकि इटली में 3000 लोगों पर यह जांच की गई थी। पहले फरवरी और मार्च 2020 में जांच की गई थी। इसके बाद मई और नवंबर में दोबारा एंटीबॉडी की जांच की गई। रिसर्च में सामने आया कि करीब 98 फीसदी लोगों में एंटीबॉडी का स्तर अधिक था।

रिसर्च में हुए खुलासे चौंकाने वाले रहे हैं। जी हां, जिन्हें लक्षण के साथ कोविड हुआ और बिना लक्षण के संक्रमित पाए गए उन दोनों में एंटीबॉडी बराबर रही। इस पर रिसर्च नेचर कम्युनिकेशन द्वारा की गई। साथ ही यह आकलन किया कि एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर कितने लोग संक्रमित हुए। इसमें खुलासा हुआ परिवार में एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हुए। हालांकि एंटीबॉडी को लेकर इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट अलग आई है। रिसर्च के प्रमुख लेखक इलारिया डोरिगटी ने कहा कि, 'हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसमें बिना लक्षण और लक्षण वालों में एंटीबॉडी को लेकर अंतर आया हो। रिसर्च में यह सामने आया है कि कुछ लोगों में एंटीबॉडी बढ़ी है। लेकिन इसका कारण है वे दोबारा संक्रमित हुए है।

तीसरी वैक्सीन का ख्याल

अगर आपको लगता है कि तीसरी लहर तक वैक्सीन का असर कम तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। एक्सपट्र्स के मुताबिक अगर आपका भीड़–भाड़ वाली जगह से कोई लेना–देना नहीं है, आप घर में ही रहते हैं तो आपको 2 डोज ही काफी है। वहीं तीसरी वैक्सीन लगाने की चर्चा फिलहाल में डॉक्टर्स के लिए हो रही है। वह बूस्टर डोज पर कार्य करेगा।

2 साल से छोटे बच्चों को भूलकर भी न लगाएं मास्क

वयस्कों और बूढ़ों को वैक्सीन लग रही है जिससे संक्रमित होने का खतरा कम हो सकता है। लेकिन क्या बच्चों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए? इसे लेकर चर्चा जारी है। तो क्या 2 साल से भी कम बच्चों को मास्क लगाना होगा? यह बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों का इस पर क्या मत है?

कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे–धीरे कम होने लगा है। लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। जिसे लेकर अभी भी सावधानियां बरतना जरूरी है। वयस्कों और बूढ़ों को वैक्सीन लग रही है जिससे संक्रमित होने का खतरा कम हो सकता है। लेकिन क्या बच्चों को भी वैक्सीन लगना चाहिए? इसे लेकर चर्चा जारी है। तो क्या 2 साल से भी कम बच्चों को मास्क लगाना होगा? यह बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों का इस पर क्या मत है?

अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वयस्क की तरह कोरोना बच्चों को भी हो सकता है। संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बेहतर उपाय है। अगर बच्चों को बाहर ले जाया जाता है तो उन्हें भी मास्क पहनाया जा सकता है लेकिन 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनाने से उन्हें घुटन हो सकती है।

अन्य विशेषज्ञ का कहना है कि 2 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को मास्क पहनाना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि बच्चों की सांस नली संकरी होती है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और मास्क लगाने से उन्हें सांस लेने में अधिक जोर लगाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है बच्चों को घर में ही रखें।

किड्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जारी गाइडलाइन में नन्हें बच्चों को मास्क न पहनने की सलाह दी गई है। अगर छोटे बच्चे मास्क पहनते हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। वह बारबार अपने चेहरे से मास्क को हटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपने मुंह और नाक पर हाथ लगाएंगे। इससे बेहतर है बच्चों को घर में ही रखा जाएं। जिससे जोखिम कम होगा।

चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों की सांस नली काफी छोटी होती है जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी आती है।

कोविड-19 मधुमेह की ला सकता है एक नई लहर

जहां मधुमेह को गंभीर कोविड परिणामों के लिए एक जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है, वहीं शोधकर्ता अब कोविड–19 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों में हाइपरग्लाइसेमिया पनपने का अंदेशा जता रहे हैं, जिसमें रक्त शर्करा का उच्च स्तर महीनों बाद तक बना रहता है। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने मार्च से मई 2020 तक इटली में कोविड–19 के लिए अस्पताल में भर्ती 551 लोगों के स्वास्थ्य का आकलन किया।

शोधपत्र के प्रमुख लेखक व नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ पाओलो फिओरिना ने कहा कि मधुमेह के इतिहास के बिना लगभग आधे रोगियों (46 प्रतिशत) में नए हाइपरग्लेसेमिया पाए गए। एक अनुवर्ती से पता चला है कि अधिकांश मामलों का समाधान किया गया था, जबकि नए हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों में से लगभग 35 प्रतिशत संक्रमण के कम से कम छह महीने बाद भी बने रहे। ग्लूकोज असामान्यताओं के कोई लक्षण वाले रोगियों की तुलना में, हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों के इलाज में भी ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता, वेंटिलेशन और गहन देखभाल की जरूरत पड़ती है।

यह शोधपत्र नेचर मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित हुआ था। टीम ने यह भी पाया कि हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों में असामान्य हार्मोनल स्तर थे।

फियोरिना ने कहा, ''हमने पाया कि वे गंभीर रूप से हाइपरिन्सुलिनमिक थे। उनके शरीर में बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन हुआ।'' उनके पास प्रो–इंसुलिन के असामान्य स्तर, इंसुलिन के अग्रदूत और बिगड़ा हुआ आइलेट बीटा सेल फंक्शन के मार्कर भी थे। आइलेट बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती और स्रावित करती हैं।

फियोरिना ने कहा, ''मूल रूप से, हार्मोनल प्रोफाइल से पता चलता है कि कोविड–19 के साथ उन रोगियों में अंत:स्रावी अग्नाशयी कार्य असामान्य है और यह ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है।''

हाइपरग्लाइसेमिक रोगियों में आईएल–6 और अन्य सहित भड़काऊ साइटोकिन्स की मात्रा में गंभीर असामान्यताएं थीं। जबकि कुछ रोगियों में ग्लूकोमेटाबोलिक असामान्यताएं समय के साथ कम हो गईं, विशेष रूप से कोविड–19 संक्रमण के बाद। ग्लूकोज का स्तर और असामान्य अग्नाशय हार्मोन का रिसाव भी कोविड के बाद की अवधि में बना रहा।

फियोरिना ने कहा, ''यह अध्ययन सबसे पहले दिखाता है कि कोविड–19 का अग्न्याशय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह इंगित करता है कि अग्न्याशय वायरस का एक और लक्ष्य है जो न केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान तीव्र चरण को प्रभावित करता है, बल्कि संभावित रूप से इन रोगियों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।'' इस शोध ने कोविड–19 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रोगियों में अग्नाशय के कार्य के मूल्यांकन के महत्व की ओर इशारा किया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

मेक्सिको में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए आर्थिक विकास पर पुनर्विचार की जरूरत

मेक्सिको सिटी। अर्थव्यवस्था मंत्री तातियाना क्लॉथियर ने कहा है कि मेक्सिको में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर में देश के 2021 के आर्थिक विकास के अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा गया है, जो पहले अनुमानित 6.3 प्रतिशत विस्तार से कम है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में घोषित आर्थिक सुधार योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्लॉथियर ने बुधवार को कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) इस साल 5.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, साल की शुरूआत में, हम 5 फीसदी से ऊपर रिबाउंड और ग्रोथ की बहुत स्पष्ट संभावना के बारे में बात कर रहे थे। फिर विभिन्न संगठन संख्या को 6.3 (प्रतिशत) रखने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा, अब हम तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे पुनर्विचार हो सकता है। हालांकि, उम्मीदें साल की शुरूआत में प्रस्तावित 5.5 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई हैं। मैक्सिकन अर्थव्यवस्था, ब्राजील के बाद लैटिन अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी, 2020 में 8.3 प्रतिशत की गिरावट, महामारी के प्रभावों के कारण 1930 के दशक के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।

इजराइल का ग्रीन पास 3 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए लागू होगा

तेल अवीव। इजराइल के कोरोनावायरस कैबिनेट ने तीन साल से अधिक उम्र के सभी वयस्कों और बच्चों पर प्रतिबंध लगाते हुए अपनी ग्रीन पास प्रणाली का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के प्रयास में, कैबिनेट ने एक बयान में मॉल और दुकानों को छोड़कर सभी स्थानों पर ग्रीन पास प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। समाचार एजेंसी ने कार्यालय के हवाले से कहा कि सिस्टम लोगों को यह दस्तावेज दिखाने की अनुमति देता है कि उन्हें टीका लगाया गया है या वायरस से मुक्त है। नए फैसले के तहत, तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को 18 अगस्त से शुरू होने वाले ग्रीन पास के तहत आने वाले स्थानों में जाने के लिए एक नकारात्मक कोरोनावायरस परीक्षण प्रस्तुत करना होगा। इनडोर स्थानों में सभा 1,000 लोगों और आउटडोर में 5,000 लोग तक सीमित होंगे। देश की 90 लाख आबादी में से लगभग 58 प्रतिशत को दोगुना-टीका लगाया गया है, जिनमें से अधिकांश को फाइजर वैक्सीन दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दैनिक नए संक्रमण 5,802 मामलों तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 405 गंभीर स्थिति में हैं।

न्यूजीलैंड ने फिजी, इंडोनेशिया को अत्यधिक जोखिम वाले देशों में किया चिन्हित

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के मंत्री क्रिस हिपकिंस ने कहा, न्यूजीलैंड ने फिजी और इंडोनेशिया को दोनों देशों में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के कारण बहुत उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में नामित किया है, जो उनके देश में यात्रा को सीमित करता है। हिपकिंस ने बुधवार को एक बयान में कहा, रात 11.59 बजे तक 15 अगस्त को, इंडोनेशिया और फिजी से न्यूजीलैंड की यात्रा की अनुमति केवल न्यूजीलैंड के नागरिकों, उनके सहयोगियों, बच्चों और आश्रित बच्चों के माता-पिता के लिए होगी, जो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं (साथ में उन माता-पिता के किसी भी बच्चे के साथ जो न्यूजीलैंड के नागरिक नहीं हैं)। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के निवासियों सहित बहुत अधिक जोखिम वाले देशों के अन्य यात्रियों को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरने से पहले एक बहुत ही उच्च जोखिम वाले देश के बाहर 14 दिन बिताने यानी क्वारंटीन करने की आवश्यकता होती है। न्यूजीलैंड सरकार ने अप्रैल में उच्च जोखिम वाली श्रेणी की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले स्थानों से बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों के न्यूजीलैंड जाने के जोखिम को कम करना है। हिपकिंस ने कहा कि बहुत उच्च जोखिम वाली श्रेणी की सूची में शुरू में भारत, ब्राजील, पाकिस्तान और पापुआ न्यू गिनी शामिल थे, जिसमें अब फिजी और इंडोनेशिया को जोड़ा जा रहा है। आंकड़े से पता चलता है कि वर्तमान में फिजी में कोविड -19 के 24,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिसका प्रकोप अप्रैल में शुरू हुआ था, जो लगातार बढ़ रहा था।

अफगानिस्तान में हिंसा से हजारों लोग अपने घरों से भागे : यूएन

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने बुधवार को कहा कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष ने हजारों लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है।
कार्यालय ने कहा कि यो लोग इस साल मई से बड़े पैमाने पर स्पाइक के साथ शत्रुता से विस्थापित हुए लगभग 390,000 लोगों का हिस्सा हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विस्थापितों में से कई काबुल और अन्य बड़े शहरों में भाग गए हैं। इसमें कहा गया है कि राजधानी शहर में अधिकांश विस्थापित लोग परिवारों और दोस्तों के साथ रह रहे हैं, वहीं कुछ बढ़ती संख्या के साथ खुले में डेरा डाले हुए हैं, जो अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच काबुल पहुंचने वाले 5,800 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को भोजन, घरेलू सामान, पानी और स्वच्छता सहायता और अन्य सहायता की आवश्यकता है। ओसीएचए ने कहा कि दस मानवीय टीमों ने बुधवार को पार्कों और अन्य खुले स्थानों में बाहर रहने वाले लोगों की जरूरतों का आकलन किया और आश्रय, भोजन, स्वच्छता और पीने के पानी की कमी वाले अतिरिक्त 4,522 विस्थापितों की पहचान की, साथ ही एक अस्थायी स्वास्थ्य क्लिनिक और मोबाइल स्वास्थ्य टीमों ने उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। ओसीएचए ने कहा कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बावजूद, मानवीय एजेंसियां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही हैं, इस साल के पहले छह महीनों में एजेंसियां 78 लाख लोगों तक पहुंची हैं। कुछ 156 गैर-सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने पूरे अफगानिस्तान में सहायता प्रदान की है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास से बौखलाया उत्तर कोरिया! दे डाली धमकी

सियोल। (एजेंसी)।

उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास को आक्रमण का पूर्वाभ्यास बताया और कार्रवाई की धमकी दी, जबकि अमेरिका ने कहा कि यह अभ्यास दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए किया गया,और ''पूरी तरह रक्षात्मक था''। सरकारी मीडिया द्वारा बुधवार को जारी बयान में बताया गया कि उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारी किम योंग चोल ने संयुक्त अभ्यास जारी रखने के लिए दक्षिण कोरिया की निंदा की और इसके जवाब में ऐसी कार्रवाई करने की धमकी दी, जिससे सियोल को ''एक मिनट में पता चल जाएगा'' कि वह सुरक्षा संकट के बीच घिर गया है। इससे पहले, उत्तर कोरिया के नेता की बहन किम यो जोंग ने कहा था, ''यह अभ्यास (उत्तर कोरियाके प्रति) अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति की सबसे ज्वलंत अभिव्यक्ति है, जिसे हमारे देश को बलपूर्वक दबाने के लिए तैयार किया गया है, और यह आत्म-विनाश का एक अवांछित कार्य है। इसने हमारे लोगों को तथा कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति को और अधिक संकट में डाल दिया है।''

उन्होंने आगाह किया कि उत्तर कोरिया भी अपनी प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करेगा।

हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि सैन्य अभ्यास कब आरंभ होगा औरन ही उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन दक्षिण कोरिया के स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि सहयोगी देश की सेना के साथ 16 से 26 अगस्त तक चलने वाले कंप्यूटर आधारित अभ्यास के पहले, सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि ये अभ्यास ''पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति'' के हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के प्रति ''कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं'' रखता है।

प्राइस ने कहा, ''हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं और हम इस दिशा में हमारे (दक्षिण कोरिया) साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे।'' उत्तर कोरिया की, अमेरिका-दक्षिण कोरियाई अभ्यासों के खिलाफ बदले की कार्रवाई की धमकी और उसकी हमलों की क्षमता को एहतियातन बढ़ाना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह अपनी हथियार परीक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू कर रहा है। चोल ने कहा कि दक्षिण कोरिया ने ''बाहरी लोगों के साथ गठबंधन करके, तनाव बढ़ाने, संबंधों में सुधार नहीं करने और टकराव '' का विकल्प चुनकर संबंध बेहतर करने के अवसर को खो दिया है। उन्होंने कहा, ''हम उन्हें मिनटों में एहसास करा देंगे कि उन्होंने कितना खतरनाक विकल्प चुना है और गलत चयन के कारण उन्हें कितने गंभीर सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ेगा।

राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना के शादी के केक का एक टुकड़ा 1,850 पाउंड में हुआ निलाम

लंदन। (एजेंसी)।

राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना के शादी के केक का एक टुकड़ा 1,850 पाउंड में नीलाम हुआ है। काल्पनिक कहानियों में सुनी जाने जैसी शादी के 40 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद यह एक निलामी में इतनी बड़ी कीमत में बिका है। केक का यह टुकड़ा शादी के 23 आधिकारिक केकों में से एक केक का है जो ब्रिटिश शाही जोड़े ने अपनी शादी में परोसा था। केक की आइसिंग (सजावट के लिए तैयार मिश्रण) और बादाम की मिठाई से तैयार बेस में शाही 'कोट ऑफ आर्म्स' को सुनहरे, लाल,नीले और चांदी से सजे विस्तृत डिजाइन को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था। यह टुकड़ा क्वीन मदर के स्टाफ की एक सदस्य मोया स्मिथ को दिया गया था जिन्होंने इसे सख्त पकड़ वाली एक फिल्म के साथ संरक्षित कर रखा था और इसपर 29 जुलाई,1981 की तारीख अंकित की थी। बीबीसी ने बुधवार को खबर दी कि स्मिथ ने टुकड़े को एक पुराने केक टिन में रखा था और इसके ढक्कन पर हाथ से बना एक लेबल चिपकाया था, जिस पर लिखा था, 'सावधानी से छुएं - राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी का केक।' उनके परिवार ने यह केक 2008 में एक संग्राहक को बेच दिया था। बोली में दुनियाभर के लोगों ने भाग लिया और केक के टुकड़े को बुधवार को गेरी लेयटन को बेच दिया गया। इस टुकड़े से महज 500 पाउंड मिलने की उम्मीद थी लेकिन निलामीकर्ताओं का कहना है कि वह इसे मिली कीमत से 'हैरान' हैं।

पूर्व-स्वास्थ्य अधिकारी ने अमेरिका की प्रारंभिक कोविड प्रतिक्रिया को दोषी ठहराया

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के एक पूर्व संघीय स्वास्थ्य अधिकारी ने कोविड -19 महामारी के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर सरकार अलग तरीके से काम करती तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को ट्रम्प प्रशासन के तहत बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व निदेशक रिक ब्राइट ने दावा किया कि उन्हें कोविड -19 के लिए एक निश्चित उपचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति के दबाव का विरोध करने के लिए बर्खास्त किया गया था। ब्राइट ने कहा कि अमेरिका और दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोगों की जान बच जाती, लोग आज भी जीवित होते अगर हमारी सरकार ने विज्ञान की बात सुनी होती। अमेरिकियों को वास्तविक जोखिम बताया होता तो आज इतने लोग नहीं मारे जाते। बीएआरडीए अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का हिस्सा है, जो कोरोनवायरस के प्रकोप के लिए संघीय सरकार की प्रतिक्रिया के केंद्र में एजेंसियों में से एक है। ब्राइट ने कहा कि अगर हमने परीक्षण शुरू किया था, तो वास्तव में एक मजबूत राष्ट्रव्यापी परीक्षण रणनीति लोगों को यह बताने के लिए कि वायरस कहां है और कौन लोग संक्रमित हैं। 2016 और 2020 के बीच बीएआरडीए का नेतृत्व करने वाले एक वायरोलॉजिस्ट ब्राइट ने सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की।

अमेरिका पाकिस्तान को केवल अफगानिस्तान में 'गड़बड़ी' से निपटने के लिए उपयोगी समझता है: इमरान खान

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान को केवल उस ''गड़बड़ी'' से निपटने के लिए ''उपयोगी'' समझता है जो उसने 20 साल की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में पीछे छोड़ी है और जब ''रणनीतिक साझेदारी'' बनाने की बात आती है, तो वह भारत को प्राथमिकता देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी एवं नाटो बलों की वापसी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान में हिंसा में खासी बढ़ोतरी देखी गई है। खान ने बुधवार को यहां विदेशी पत्रकारों से कहा, ''पाकिस्तान को केवल उस गड़बड़ी से निपटने के संदर्भ में उपयोगी समझा जाता है, जो सैन्य समाधान खोजने की कोशिश के 20 साल बाद पैदा हुई है।'' खान ने संवाददाता सम्मेलन में मौजूद एक पत्रकार से कहा कि अमेरिका ने जब से भारत के साथ ''रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है, वह

पाकिस्तान के साथ अलग व्यवहार कर रहा है।

पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि बाइडेन ने जनवरी में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री खान से बातचीत नहीं की है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने हाल में इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि अफगानिस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस्लामाबाद को महत्वपूर्ण देश मानने के बावजूद प्रधानमंत्री खान से संपर्क करने को लेकर राष्ट्रपति बाइडन अनिच्छुक हैं। युसूफ ने कहा था कि अगर अमेरिकी नेता देश के नेतृत्व की अनदेखी करते रहे, तो इस्लामाबाद के पास अन्य ''विकल्प'' हैं। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में शांति बहाल करने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और चाहता है कि पाकिस्तान वह भूमिका निभाए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस सप्ताह पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से फोन पर बात की और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस वार्ता के बाद पेंटागन ने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के नेतृत्व से अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास तालिबान आतंकियों की पनाहगाहों को खत्म करने की आवश्यकता पर बात की है, क्योंकि इन सुरक्षित ठिकानों से अफगानिस्तान में और ज्यादा असुरक्षा और अस्थिरता पैदा हो रही है। अफगानिस्तान और अमेरिका तालिबान लड़ाकों को पनाह देने और अन्य सहायता मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते रहे हैं।

अफगान नेतृत्व को तय करना है कि क्या उनमें लड़ने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में लेने के बीच व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि यह अफगान नेतृत्व को तय करना है कि क्या उनके पास जवाबी कार्रवाई की राजनीतिक इच्छाशक्ति है या नहीं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 60 प्रतिशत हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बाइडन प्रशासन ने कहा कि अफगान राष्ट्रीय बलों के पास तालिबान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की क्षमता और हथियार हैं। अमेरिका ने दो दशकों तक अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सेना को प्रशिक्षण दिया।व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के पास वापस लड़ने के उपकरण, पर्याप्त सैनिक और प्रशिक्षण है। उन्हें जिसकी जरूरत है वह सब उनके पास है। उन्हें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या उनमें लड़ाई का जवाब देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है और क्या लड़ाई लड़ने के लिए नेताओं के तौर पर एकजुट होने की क्षमता है।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्धग्रस्त देश में बिगड़ी सुरक्षा परिस्थितियों पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा, ''हम अफगान बलों के साथ हवाई हमले करते रहेंगे। जैसा कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है तो अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा और देश का भविष्य असल में उनके कंधों पर है।'' विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में उसके प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की रणनीति बदल रही है। उन्होंने कहा, ''राष्ट्रपति ने हमारी सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया। इसमें अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए हमारे समर्थन पर कुछ नहीं कहा गया और हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करते रहेंगे, अभी हम कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिए बात करते हैं।'' प्राइस ने कहा कि दोहा में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमी खलीलजाद और उनकी टीम ने विस्तारित ट्रोइका की बैठक में भाग लिया। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों ने तालिबान पर हिंसा कम करने, गंभीरता से और तुरंत अफगान शांति वार्ता में शामिल होने के लिए जोर देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, ''हम बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर सतर्क हैं। और अभी हमारा ध्यान मैदान पर अफगान बलों का सहयोग करने पर है।

चीन की जेल में 11 साल तक कैद रहेगा कनाडा के नागरिक, कनाडा के विरोध पर चीन रहा बेअसर

बीजिंग। (एजेंसी)।

चीन ने कनाडाई नागरिकों को चीनी अदालतों द्वारा दी गयी कड़ी सजा पर कनाडा के विरोध को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। इन मामलों को चीन की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनी हुआवै की एक शीर्ष अधिकारी को वैंकूवर में गिरफ्तार करने से जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में चीन के दूतावास ने ओटावा को निराधार आरोप लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जो ''चीन की न्यायिक संप्रभुत्ता में घोर हस्तक्षेप'' है। उन्होंने अपने बयान में कहा, ''इस तरह के आरोप बेहद अनुचित हैं, बेहद बेतुके और अत्यधिक अहंकारी है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।''

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने उद्यमी माइकल स्पैवर की सजा को बुधवार को ''बिल्कुल अस्वीकार्य और अनुचित'' बताया था। उन्होंने ''कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी'' का हवाला दिया और कहा था कि ''मुकदमा अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा आवश्यक न्यूनतम मानकों को भी संतुष्ट नहीं करता है।'' उन्होंने कहा, ''स्पैवर के साथ ही मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए माइकल कोवरिग के लिए हमारी शीर्ष प्राथमिकता उनकी तत्काल रिहाई है। हम उन्हें जल्द से जल्द घर लाने के लिए चौबीसों घंटे काम करते रहेंगे।'' स्पैवर और पूर्व राजनयिक कोवरिगो उस समय हिरासत में लिया गया जब इससे पहले ईरान पर व्यापार प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघनों के संबंध में हुआवै की कार्यकारी अधिकारी को अमेरिका के अनुरोध पर एक दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पैवर और कोवरिग को मनमाने तरीके से हिरासत में लेने से इनकार किया और कहा कि उनके अधिकार ''पूरी तरह सुरक्षित'' हैं। मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कनाडा पर चीन पर दबाव बनाने के लिए उसके सहयोगियों को एकजुट करके ''मेगाफोन कूटनीति'' अपनाने का आरोप लगाया।

तालिबान ने अपने लड़ाको की डाली ऑनलाइन वीडियो और तस्वीरें, कर रहे अपनी शक्ति का प्रदर्शन!

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी के बीच तालिबान ने बृहस्पतिवार को काबुल के निकट एक और प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया और इसे मिलाकर यह आतंकवादी संगठन अब तक दस प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। काबुल के दक्षिणपश्चिम में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजनी में उग्रवादियों ने श्वेत झंडे फहराए। दो स्थानीय अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि शहर के बाहर स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान और खुफिया ठिकाने पर छिटपुट लड़ाई अब भी चल रही है।

तालिबान की ओर से ऑनलाइन वीडियो और तस्वीरें डाली गईं जिनमें उसके लड़ाके गजनी प्रांत की राजधानी गजनी में नजर आ रहे हैं। कई दिनों से जारी लड़ाई पर अफगान सुरक्षा बल और सरकार कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं हैं। लगातार बढ़त बना रहे तालिबान से काबुल को सीधे कोई खतरा नहीं है लेकिन उसकी तेज बढ़त सवाल खड़े करती है कि अफगान सरकार अपने पास बचे इलाकों को आखिर कब तक नियंत्रण में रख पाएगी। संभवत~ सरकार राजधानी और कुछ अन्य शहरों को बचाने के लिए अपने कदम वापस लेने पर मजबूर हो जाए क्योंकि लड़ाई के कारण विस्थापित हजारों लोग काबुल भाग आए हैं और खुले स्थानों और उद्यानों में रह रहे हैं। गजनी प्रांत के परिषद सदस्य अमानुल्ला कामरानी ने एपी को बताया कि शहर के बाहर बने दो बेस अब भी सरकारी बलों के कब्जे में हैं। इस बीच

अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक लश्कर गाह में लड़ाई तेज हो गई है। हेलमंड से सांसद नसीमा नियाजी ने बताया कि बुधवार को आत्मघाती कार बम हमले में राजधानी के क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया था।

बृहस्पतिवार को तालिबान ने मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ ने नजदीक के गवर्नर्स कार्यालय में शरण ली जो अब भी सरकारी बलों के कब्जे में है। नियाजी ने बताया कि प्रांतीय कारागार पर भी आत्मघाती कार बम हमला हुआ हालांकि इस पर अब भी सरकारी बलों का कब्जा है। लेकिन तालिबान बीते एक हफ्ते में अपने सैकड़ों आतंकवादियों को छुड़वा चुका है तथा हथियारों और वाहनों पर कब्जा कर चुका है। नियाजी ने इलाके में हवाई हमलों की निंदा की और आशंका जताई कि इसमें आम नागरिक मारे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ''तालिबान के लड़ाके स्वयं को सुरक्षित करने के लिए आम लोगों के घरों का इस्तेमाल करते हैं और सरकार नागरिकों की परवाह किए बगैर हवाई हमले कर रही है।'' माना जा रहा है कि अमेरिकी वायु सेना हवाई हमलों में अफगान बलों की मदद कर रही है। अमेरिकी बम हमलों में कितने लोग मारे गए हैं इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।

रूस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, आठ लोग लापता, तलाश जारी

मॉस्को। (एजेंसी)।

पर्यटकों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर बृहस्पतिवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी के निकट स्थित झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दल हेलीकॉप्टर में सवार आठ लोगों की झील में तलाश कर रहे हैं। वहीं कम से कम आठ अन्य लोग हादसे में कथित तौर पर बच गए हैं। हेलीकॉप्टर क्रोनोटस्की नेचर रिजर्व में नीचे की ओर चला गया था। क्षेत्रीय प्रशासन ने बताया कि कार्यकर्ता कुरील झील में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। यह झील ज्वालामुखी फटने के बाद बनी है। सरकारी समाचार एजेंसी 'आरआईए नोवोस्ती' के अनुसार, रूस के आपात मामलों संबंधी मंत्रालय ने बताया कि 'एमआई-8' हेलीकॉप्टर में 13 यात्री और चालक दल के तीन सदस्य सवार थे। इनमें से आठ लोग बच गए हैं, जिनमें से दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं, समाचार एजेंसी 'द इंटरफैक्स' ने बताया कि हादसे में बचे लोगों में दो गंभीर रूप घायल हुए है और उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। 'नेचर रिजर्व' में रेंजरों ने झील के पास हेलीकॉप्टर के आने और फिर सतह से टकराने की आवाज सुनने की सूचना दी और कहा कि उन्होंने तुरंत दो नावों को दुर्घटनास्थल पर भेज दिया। कामचटका सरकार ने एक वीडियो साक्षात्कार जारी किया जिसमें बचे लोगों में से एक, विक्टर स्ट्रेलकिन ने कहा, 'पानी सचमुच ठंडा था। कोहरा कम था।' उन्होंने कहा कि बचाव नौकाएं समय पर पहुंच गई। उन्होंने कहा, 'मैं खुद को और नहीं बचा सका। मेरे स्नीकर्स जूते मुझे नीचे खींच रहे थे, मैं मुश्किल से उन्हें उतारने में कामयाब रहा। मैं पेट के बल तैर नहीं सकता था और मुझे एहसास हुआ कि इन स्थितियों में मैं ज्यादा देर तक लटक नहीं पाऊंगा। सौभाग्य से, पांच मिनट के भीतर, लोगों के साथ दो नावें आ गईं।' रूसी मीडिया की खबरों में हेलीकॉप्टर में सवार पर्यटकों की राष्ट्रीयताओं के बारे में नहीं बताया लेकिन इनमें कहा गया है उनमें से ज्यादातर मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग से थे। क्षेत्रीय अभियोजक उड़ान सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहे हैं।

गैरकानूनी बायोडीजल की बिक्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.90 करोड़ का माल जब्त

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद, स्टेट मोनिटरिंग सेल ने गैरकानूनी बायोडीजल की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रु 6.90 करोड़ का माल-सामान जब्त करने के साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में तीन आरोपी फरार हो गए। राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया के आदेशानुसार स्टेट मोनिटरिंग सेल ने सूरत जिले के मांडवी पुलिस थानान्तर्गत करंज जीआईडीसी मोलवण पाटिया के निकट एक फैक्ट्री और फाटकोल गांव की सीमा पर मांडवी-कीम रोड के निकट स्थित खुली जगह पर गैरकानूनी बायोडीजल के बिक्री स्थल पर छापा मारा। पुलिस ने घटनास्थल से रु 10717500 कीमत के 142900 लीटर बायोडीजल समेत रु 69075624 का माल-सामान जब्त कर लिया। साथ ही घटनास्थल से 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीन फरार हो गए। राज्य में गैरकानूनी बायोडीजल के खिलाफ यह सबसे बड़ी छापेमारी है। पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले और शहर द्वारा स्थानीय स्तर पर अलग अलग टीमें बनाकर गैरकानूनी बायोडीजल की बिक्री करने वाले पंप या अन्य स्थलों पर रेड की जा रही है। जुलाई से 10 अगस्त 2021 तक कुल 311 मामले दर्ज कर 455 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आवास योजना के ड्रो में गड़बड़ी के आरोप में वीएमसी के दो अधिकारी गिरफ्तार

क्रांति समय दैनिक

वडोदरा, शहर की नवापुरा पुलिस ने आवास योजना के ड्रो में गड़बड़ी के आरोप में वडोदरा महानगर पालिका के दो अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हिरासत में लिए गए अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाय गया है। जानकारी के मुताबिक वडोदरा महानगर पालिका के शहर अभियंता शैलेष मिस्त्री ने नवापुरा पुलिस थाने में अधिशाषी अभियंता प्रमोद वसावा और एमआईएस एक्सपर्ट निशित पीठवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों ने ड्रो में घोषित लाभार्थियों के नाम की सूची बदलकर नई सूची अपलोड कर दी थी। शैलेष मिस्त्री की शिकायत के आधार पर नवापुरा पुलिस ने प्रमोद वसावा और निशित पीठवा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरूकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त से 9 अगस्त के दौरान राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत 7 अगस्त को वडोदरा महानगर पालिका ने गुजरात सरकार के राज्यमंत्री योगेश पटेल की उपस्थिति में शहर के सयाजीराव नगर गृह में आवास योजना के 382 आवासों का ड्रो किया था। आवास आवंटन के ड्रो होने के एक घंटे बाद प्रमोद वसावा और निशित पीठवा ने 42 लाभार्थियों के नाम पर बदलकर नई सूची ऑनलाइन अपलोड कर दी थी। इस मामले की जांच महानगर पालिका के शहर अभियंता शैलेष मिस्त्री को सौंपी गई थी। शैलेष मिस्त्री की जांच में लाभार्थियों के नाम बदले जाने का खुलासा होने के बाद प्रमोद वसावा और निशित पीठवा के खिलाफ वडोदरा के नवापुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा गई थी।

क्रांति समय फाउंडेशन (NGO)

वॉट्सएप पर विवादित मैसेज को लेकर सेना के निवृत्त जवान की हत्या

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद, जिले के बावला में वॉट्सएप पर विवादित मैसेज को लेकर सेना के निवृत्त जवान और एक पुलिसकर्मी पर तीक्ष्ण हथियार से हमला किया गया। इस घटना में निवृत्त जवान की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि पुलिस जवान घायल हो गया, जिसे अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरूकी है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद जिले के बावला स्थित भाग्यश्री सोसायटी में सेना के निवृत्त जवान जयपालसिंह गंभीरसिंह गढ़वी की तीक्ष्ण हथिया से गोदकर हत्या कर दी गई। जबकि बीचबचाव करने वाले अहमदाबाद पुलिस के जवान कृणाल नवलसिंह गढ़वी को घायल कर दिया। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक जयपालसिंह गढवी और आरोपी हसमुख गढ़वी दोनों रिश्तेदार हैं। हसमुख की पत्नी रेणुका गढ़वी सरपंच थी, जिसे किन्हीं कारणों से सरपंच पद से सस्पैंड कर दिया गया था। आरोपियों को लगता था कि मृतक जयपालसिंह की वजह से रेणुका को सस्पैंड किया गया था। बीती रात गढ़वी समाज के वॉट्सएप ग्रुप में किसी मैसेज को लेकर मामला बिगड़ा और इसे लेकर हसमुख गढ़वी और जयपाल गढ़वी के बीच कहासुनी हुई थी। जिसके बाद जयपाल और कृणाल बगल की सोसायटी में रहनेवाले हसमुख गढ़वी के घर गए थे। जहां हसमुख ने जयपाल पर तीक्ष्ण हथियार से हमला कर दिया। जिसमें जयपालसिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि पुलिस कांस्टेबल कृणाल गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बावला पुलिस ने हसमुख गढ़वी, उसकी पत्नी रेणुका गढ़वी, पुत्र पृथ्वी गढ़वी और भाई सुरेश गढ़वी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर हसमुख गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के अन्य फरार आरोपियों की पुलिस ने खोजबीन शुरूकी है।

सार-समाचार

गुजरात के २ आईपीएस समेत ६ पुलिसकर्मियों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय करेगा सम्मानित

अहमदाबाद, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने श्रेष्ठ जांच कार्यवाही के लिए गुजरात के 2 आईपीएस समेत 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। श्रेष्ठ कार्यवाही के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 15 अगस्त को गुजरात के इन 6 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गुजसीटोके आरोपियों के खिलाफ जांच में श्रेष्ठ कार्यवाही के लिए इन 6 पुलिसकर्मियों को चुना गया है। जिसमें सूरत के 3, अहमदाबाद के 2 और जामनगर का एक पुलिसकर्मी शामिल हैं। सूरत की डीसीपी विधि चौधरी, पीआई महेन्द्र सालुंके और पीआई मंगुभाई ताडु को पुरस्कृत किया जाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पीआई दर्शन बारड और पीआई एवाय बलोच के अलावा जामनगर के एसीपी नितेश पांडेय को केन्द्रीय गृह मंत्रालय सम्मानित करेगा।

रिसोर्ट में लगी आग में 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे, पुलिस ने जांच शुरूकी

राजकोट, शहर के कालावाड रोड स्थित निराली रिसोर्ट में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग की इस घटना में रिसोर्ट में काम करने वाले 8 जितने कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को राजकोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एफएसएल की मदद से पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक राजकोट के कालावाड रोड स्थित निराली रिसोर्ट में एक रूम अचानक आग भड़क उठी। रिसोर्ट में कैटरिंग का काम करने वाले कर्मचारी इस रूम में रहते हैं। आग की इस घटना में राजु लबाना, लोकेश लबाना, हितेश लबाना, देवीलाल लबाना, लक्ष्मण लबाना, दीपक लबाना, शांतिप्रसाद लबाना और चिराग लबाना गंभीर रूप से झुलस गए। सभी राजस्थान के डुंगरपुर के निवासी हैं। सभी घायलों का राजकोट के सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। आग में झुलसे कर्मचारियों को कहना है कि घटना के वक्त दरवाजा बाहर से बंद था। कर्मचारियों के इस खुलासे के बाद पुलिस ने एफएसएल की मदद से मामले की जांच शुरूकी है।

साबरमती नदी पर एक और ब्रिज बनेगा, अचेर गाम और केम्प सदर बाजार को जोडेगा

अहमदाबाद, शहर में अचेर गाम को केम्प सदर बाजार से जोड़ने वाला एक ब्रिज बनेगा। अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा रु 250 करोड़ के खर्च से यह ब्रिज साबरमती नदी पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच अतिरिक्त कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साबरमती, राणीप समेत चांदखेडा इत्यादि में रहनेवाले लोगों को सीधे एयरपोर्ट आने-जाने में सरलता होगी। अभी इन इलाकों से एयरपोर्ट जाने के लिए सुभाष ब्रिज, शाहीबाग अंडर ब्रिज और डफनाला का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन नया ब्रिज बनने से एयरपोर्ट आने-जाने में करीब 10 किलोमीटर की दूरी कम होगी। दरअसल अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा साबरमती नदी पर अचेर से ताज सर्कल को जोड़ता ब्रिज बनाने की दरखास्त 12 वर्ष पहले की गई थी। लेकिन ताज होटल के पीछे रिहायशी इलाकों में कुछ बिल्डर और नेताओं की स्कीमें और जमीन होने की वजह से निर्दिष्ट यह मामला लटका पड़ा था।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

गृह सचिव बने रहेंगे अजय कुमार भल्ला, सरकार ने बढ़ाया एक साल का कार्यकाल

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा को एक साल का विस्तार दिया है। अजय कुमार भल्ला एक साल और अपने पद पर बने रहेंगे। अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था। भल्ला अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर नियुक्त हुए थे। आपको बता दें कि अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अजय कुमार भल्ला ऊर्जा मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं। गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी थे। कोरोना महामारी के दौरान अजय कुमार भल्ला ने खूब सक्रियता दिखाई है। वह लगातार राज्यों से संपर्क में रहे हैं।

कोरोना मामलों में उछाल के डर से, महाराष्ट्र ने स्कूल को खोलने की योजना टाली

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार की देर रात हुई कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक के बाद स्कूलों को फिर से खोलने की योजना टाल दी है। पहले राज्य में स्कूल 17 अगस्त से खोले जाने थे। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में और टास्क फोर्स के सदस्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में हुई बैठक, स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में फैसला किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ स्कूल, जहां कोरोनोवायरस से कोई खतरा नहीं है, कार्य करना जारी रखेंगे, राज्य के अन्य सभी स्कूल मार्च 2020 से बंद हैं। स्कूलों को 17 अगस्त से फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि पंजाब जैसे कुछ अन्य राज्यों में, जहां स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, वहां किशोर कोविड रोगियों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मत है कि चूंकि संक्रमण की चपेट में आने वाले बच्चों के लिए कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय तुरंत नहीं लिया जाना चाहिए।

बिहार में अब थैले के जरिए घर-घर दस्तक देगी भाजपा

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब थैले के जरिए बिहार के निर्धन परिवारों के घरों पर दस्तक देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगे थैले को भाजपा अब आम लोगों के बीच बांटने वाली है।
भाजपा के इसके पीछे तर्क है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली राशन को घरों तक लाने में कई लोगों को दिक्कत हो रही है। यह थैला इस परेशानी से लोगों को निजात देगा।

भाजपा के एक नेता की मानें तो पार्टी कम से कम 50 लाख घरों तक इस थैले के जरिए पहुंचने की योजना बनाई है। इसके जरिए भाजपा यह भी बताने की कोशिश करेगी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक महीने मिलने वाला पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी घर-घर तक बताया जाएगा। भाजपा का यह अभियान 14 जुलाई से प्रारंभ होगा। उस दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय से इसकी शुरूआत होगी और उसके बाद 16 अगस्त से 21 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालयों में इस थैले का वितरण होगा। इस अभियान के तहत कम से कम 50 लाख परिवार को एक-एक थैला दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद को एक टागरेट दिया गया है। इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पार्टी के कई पदाधिकारियों को जिम्मदारी दी गई है।

यूपी कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले की जांच का आदेश दिया

प्रयागराज। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत ने पुलिस को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आदेश जारी किए गए हैं। बुधवार को एसीजेएम (प्रयागराज) नम्रता सिंह ने छावनी, प्रयागराज के थाना प्रभारी को कुछ बिंदुओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज द्वारा उपमुख्यमंत्री को जारी उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की डिग्री की प्रामाणिकता शामिल है। मामले में आवेदक दिवाकर त्रिपाठी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक याचिका में मौर्य के खिलाफ विभिन्न स्थानों से पांच चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री के कथित उपयोग के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। दूसरा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री ने फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप भी हासिल किया। एसीजेएम ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त तय की है।

राहुल ने सरकार के खिलाफ मार्च का नेतृत्व किया, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संसद सदस्यों और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने मानसून सत्र में कटौती के विरोध में गुरुवार को संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। सांसदों ने बैनर और तख्तियां लेकर कृषि कानूनों को वापस लेने का आह्वान किया और इनमें लोकतंत्र की हत्या लिखा हुआ था।

विरोध का नेतृत्व करते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया, हमें प्रेस से बात करने के लिए यहां आना होगा क्योंकि विपक्ष में हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के 60 फीसदी लोगों की आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया और कल राज्यसभा में उन्हें (महिला सांसदों को) पीटा गया। संसद का सत्र खत्म हो गया है, लेकिन जहां तक देश के 60 फीसदी हिस्से का सवाल है, तो संसद का कोई सत्र नहीं हुआ है। विपक्षी नेताओं ने मांग की कि कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और कहा कि वे मानसून सत्र को कम करने का विरोध कर रहे हैं जो शुक्रवार तक होने वाला था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, विपक्ष को सदन में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला और महिला सांसदों के खिलाफ कल की घटना लोकतंत्र के खिलाफ थी क्योंकि ऐसा लगा कि हम (विपक्ष) पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं। बुधवार की घटनाओं के बारे में शिकायत करने के लिए विपक्षी नेताओं के सदन के सभापति से मिलने की संभावना है। बुधवार को संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब वे सदन में बीमा विधेयक का विरोध कर रहे थे, तो महिला सांसदों के साथ पुरुष मार्शलों ने मारपीट की। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने कहा, मुझे पुरुष मार्शलों द्वारा धक्का दिया गया और मैं फूलो देवी नेताम पर गिर गई। वह भी सदन के फ्लोर पर गिर गईं। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा, अपने पूरे संसदीय करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि जिस तरह से आज उच्च सदन में महिला सांसदों पर हमला किया गया। 40 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बाहर से सदन में लाया गया। यह बहुत दुखद और दर्दनाक है। यह लोकतंत्र पर हमला है।

संसद में सत्ता तथा विपक्ष के बीच गतिरोध को मायावती ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

लखनऊ (एजेंसी)।

संसद में सत्ता तथा विपक्ष के बीच गतिरोध को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मायावती ने एक ट्वीट में कहा, '' देश की संसद तथा इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों में सत्ता व विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव व तीव्र विरोध आदि देखे हैं, किन्तु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा।'' गौरतलब है कि संसद का 19 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से दो दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पेगासस जासूसी मामले और तीन कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में जहां मात्र 22 प्रतिशत, वहीं राज्यसभा में महज 28 प्रतिशत ही कामकाज हो पाया।

बोम्मई की पहली सियासी परीक्षा 3 सितंबर को होगी

बेंगलुरु (एजेंसी)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अब से लगभग तीन सप्ताह में अपने पहले लिटमस टेस्ट का सामना करेंगे, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने 3 सितंबर को राज्य में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा की है। बेलगावी में 58 वार्ड, कलबुर्गी में 55 वार्ड और हुबली और धारवाड़ निगमों के 82 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। आयोग ने बुधवार को चुनाव की घोषणा की है। चुनाव लंबित थे क्योंकि परिसीमन और वार्ड-वार आरक्षण का मामला न्यायालय के समक्ष था। ढाई साल से अधिक समय से ये चुनाव लंबित हैं। 16 अगस्त को अधिसूचना जारी कर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान की तारीख 3 सितंबर निर्धारित की गई है। वोटों की गिनती 6 सितंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्नाटक सरकार से सवाल किया था। जिसने कोविड के कारण चुनाव कराने पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने यह कहते हुए खिंचाई की थी कि अगर लोग मंदिरों और अन्य जगहों पर जा सकते हैं तो वोट देने क्यों नहीं जा सकते। हालांकि, बोम्मई के लिए चुनाव की पहली परीक्षा होने जा रहे हैं क्योंकि बेलागवी, कलबुर्गी और हुबली-धारवाड़ निगम उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में स्थित हैं, जिन्हें भाजपा का गढ़ माना जाता है।

करीब 15 करोड़ बच्चे एवं युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर: धर्मेन्द्र प्रधान

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे एवं युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं और करीब 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिके नीचे है। प्रधान ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान 'रोजगार सृजन एवं उद्यमिता' विषय पर अपने संबोधन में यह बात कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, '' अगर हम सरकारी, निजी एवं धर्मार्थ स्कूलों, आंगनवाड़ी, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कौशल से जुड़ी पूरी व्यवस्था में 3 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों एवं युवाओं की संख्या पर नजर डालें तब यह संख्या 35 करोड़ होती है जबकि देश में इस आयु वर्ग की आबादी 50 करोड़ है।''

उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे एवं युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं। प्रधान ने कहा कि आजादी के बाद करायी गई जनगणनना में यह पाया गया कि आबादी का 19 प्रतिशत हिस्सा साक्षर है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार देश में साक्षरता दर 80 प्रतिशत पहुंच गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 प्रतिशत आबादी या करीब 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिके नीचे है।

इस दिशा में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधान ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि अगले 25 वर्षो में उन लक्ष्यों को हासिल करने का खाका है जब हम आबादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार हमारी सरकार ने शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ा है और यह आजीविका की दिशा में नयी पहल को रेखांकित करता है।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले विपक्ष के नेता, खड़गे बोले- सरकार ने कानूनों में कमी बताने का नहीं दिया समय

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है लेकिन अंतिम दिन की घटना को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, सपा के रामगोपाल यादव समेत तमाम नेता मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद विपक्षी दल ने नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया।

इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 15 पार्टियों के नेताओं ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमने उपराष्ट्रपति को वरिष्ठ नेता शरद पवार समेत सभी नेताओं ने सदन की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

खड़गे ने कहा कि सरकार ने सदन में हर 10 मिनट में एक बिल पास किया है। किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। यहां तक की कानूनों में क्या कमियां है यह भी बताने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद 6 घंटे की बातचीत के बाद हम सभी नेताओं ने मिलकर संविधान संशोधन बिल पर सरकार का साथ दिया। क्योंकि हम चाहते थे कि संसद चले।

अकाउंट बंद करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन: थरूर

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कांग्रेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच जारी खींचतान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने गुरुवार को कहा कि खातों को बंद करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, थरूर ने कहा, खातों को स्वचालित रूप से लॉक करना एक चरम कदम है जो भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकता है। उन्होंने कहा, मैं ट्विटर की स्थिति को समझता हूं कि उसके पास भारतीय कानून और ट्विटर नीति का उल्लंघन करने वाले खातों को ब्लॉक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि कानून वही है, नीति की समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप, हत्या और जल्दबाजी में किए गए दाह संस्कार ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यह त्वरित कार्रवाई की मांग करता है, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस मानवीय त्रासदी में शामिल लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, दोहरे मानकों की धारणा मामले को बदतर बना देती है। जब भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हाथरस बलात्कार पीड़िता (भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए का उल्लंघन करते हुए) की तस्वीर पोस्ट की, तो ट्विटर ने

उसका खाता बंद नहीं किया। एससी आयोग ने 2 अगस्त को पीड़ित के परिवार की एक तस्वीर पोस्ट की, कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख विपक्षी नेता के खिलाफ की गई ट्विटर की कार्रवाई चयनात्मकता और पूर्वाग्रह की स्पष्ट चिंता पैदा करती है। मैं राहुल गांधी खाते को बहाल करने, स्वत- निलंबन की नीति की समीक्षा करने और सार्वजनिक चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह करता हूं। लड़की के साथ जो हुआ उस पर ध्यान दें, तस्वीर पर नहीं! कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के बाद, ट्विटर ने अब पार्टी के आधिकारिक हैंडल को लॉक कर दिया है।

अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा चीन, भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में कर रहा मजबूत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं है। भले ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और राजनैतिक बातचीत जारी है लेकिन गतिरोध को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। पिछले साल मई-जून में भारत और चीन की सेना लद्दाख में आमने-सामने हो गई थी। चीन लगातार अपनी विस्तार वादी नीति को बढ़ाने की कोशिश में है। वह भारत के कई हिस्सों पर लगातार अपना दावा करता है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर चीन भारत से चाहता क्या है? कुछ विशेषज्ञों की माने तो उनका दावा है कि चीन भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में मजबूत कर रहा है। लद्दाख के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से एक गोगरा पोस्ट से फेस ऑफ की स्थिति को कम करने के लिए चीन के साथ एक समझौते की स्थिति में भारत पहुंच गया है। हालांकि अब तक चीन की ओर से कोई अधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़े गतिरोध के बाद भारत ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस क्षेत्र में मिलिट्री एसेटस् को लेकर बड़ा खर्च आया है। भारत सरकार अतिरिक्त हथियार, गोला-बारूद और लॉजिस्टिक आइटम खरीद रही है। दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को चीन लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि चीन लगातार भारत को लद्दाख में उलझाकर रखा हुआ है। लद्दाख के जरिए चीन लगातार भारत पर दबाव बनाता रहेगा। इसके साथ-साथ हथियार की खरीदारी में भारत ज्यादा शामिल रहेगा जिससे कि यहां की अर्थव्यवस्था भी दबाव में रहेगी। चीन अपनी नौसेना में हर साल 20 से 25 युद्धपोत और पनडुबियां जोड़ रहा है जो कि भारतीय नौसेना की तुलना में अधिक भार वाले जहाज है। इसके साथ-साथ वह हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की कोशिश में है। एक रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक आने वाले 10 सालों में चीन एक स्थाई युद्ध वाहक हिंद महासागर में तैनात कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर भारत के अध्यक्षीय वक्तव्य को स्वीकार किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की खुली चर्चा के बाद, भारत के अध्यक्षीय वक्तव्य में चीन को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की गई है कि 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन में सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने एक वीडियो संदेश में कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर हुई उच्चस्तरीय बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। तिरुमूर्ति ने कहा, सुरक्षा परिषद की इस बैठक में पहली बार समुद्री सुरक्षा की समग्र अवधारणा पर अध्यक्षीय वक्तव्य को स्वीकार किया गया है। इस वक्तव्य में समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के उल्लेख के अलावा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1982 का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है।

पंद्रह देशों के निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए अध्यक्षीय वक्तव्य (पीआरएसटी) में सुरक्षा परिषद ने पुष्टि की है कि 10 दिसंबर 1982 को अमेरिका में हुए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) में परिलक्षित अंतरराष्ट्रीय कानून समुद्री गतिविधियों पर लागू होने वाले कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है। भारत के इस अध्यक्षीय वक्तव्य को सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए जाने को चीन के लिये कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो दक्षिण चीन सागर समेत विभिन्न समुद्री क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इससे पहले, सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की थी।

उच्चतम न्यायालय ने नारायण साई को दो हफ्ते का फर्लो देने के आदेश पर लगायी रोक

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों का फर्लो देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। साई दुष्कर्म के एक मामले में दोषी है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया। इस याचिका में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 24 जून को नारायण साई को फर्लो की मंजूरी दी थी। इससे पहले दिसंबर 2020 में उच्च न्यायालय ने साई की मां की तबीयत खराब होने के कारण उसे फर्लो दी थी। सूरत की एक अदालत ने नारायण साई को 26 अप्रैल 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (षड़यंत्र)

के तहत दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी।

साई को उसकी और उसके पिता आसाराम की पूर्व अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी। पीड़िता की बहन ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)